

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जनवरी 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO-P-BHUMN/2006/18181, DAVP NO-129888, POSTAL REG. NO. :- PT-35



जातिगत जनगणना

ओबीसी पर दलीय राजनीति !

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिंदी न्यूज़ पोर्टल

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज़
24 घंटे आपके साथ



आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा



www.kewalsach.com



BHIM UPI

G Pay

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605



जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ



सत्येन्द्र नाथ बोस
01 जनवरी 1894



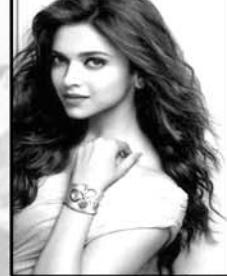
नाना पाटेकर
01 जनवरी 1951



विद्या बालन
01 जनवरी 1978



ममता बनर्जी
05 जनवरी 1955



दीपिका पादुकोण
05 जनवरी 1986



बिपाशा बसु
07 जनवरी 1979



ए.आर. रहमान
08 जनवरी 1966



फराह खान
09 जनवरी 1965



हृतीक रोशन
10 जनवरी 1974



राहुल द्रविड़
11 जनवरी 1973



स्वामी विवेकानन्द
12 जनवरी 1863



प्रियंका गांधी
12 जनवरी 1972



राकेश शर्मा
13 जनवरी 1963



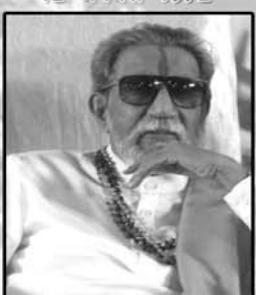
मायावती
15 जनवरी 1956



जावेद अख्तर
17 जनवरी 1945



सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी 1897



बाल ठाकरे
23 जनवरी 1926



बॉबी दिओल
27 जनवरी 1967



लाला लाजपत राय
28 जनवरी 1865



प्रिति जिंटा
31 जनवरी 1975

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303,
Kokar Chowk, Ranchi-834001
(Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla,
Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near. md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880,
09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

W AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & Inner Page	60,000/-	35,000/-

- एक साल के स्थिरित विज्ञापन पर पत्रिका के वेबसाइट www.kewalsach.com के फ्रंट पर भी विज्ञापन स्थिरता आपका वेबसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
- एक साल के स्थिरित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
- आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
- पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

श्रीराम-दामायण पट

राजनीति

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com



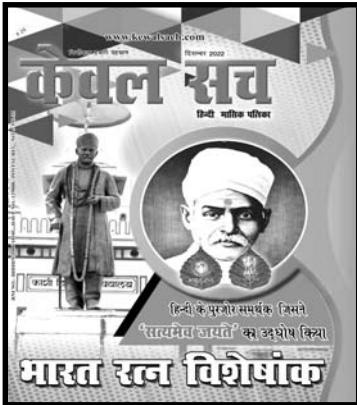
किसी भी धर्म एवं उसकी ग्रंथों पर अभद्र टिप्पणी करना तथा उसके मूल को अपनी भाषा में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना कठुनी रूप से भी प्रतिवर्धित होता चाहिए। विहार की राजनीति में जाति एवं धर्म का खास महत्व है और वह भी तब जब विपक्ष में भाजपा हो।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमेशा भगवन श्रीराम पर गलत टिप्पणी की है तथा अब राष्ट्रीय जनता दल के कोठे के शिक्षा मंत्री ने देखी हात समारोह में भगवन श्रीराम के रामायण ग्रंथ पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसपर देश के चर्चित रामकथा वाचक एवं भाजपा ने पुरजोर विरोध किया है। खुद को फंसता देख शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार चंद्रशेखर सिंह ने यह कहा कि तुलसीदास रवित रामायण में ‘दोल-गवार-शुद्ध-पशु-नरी, सकल तड़ना के अधिकारी’ में दलित वर्ग एवं महिलाओं पर अभद्र बात लियी गयी है, मैंने उसपर अपनी बात कही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है जिसका शांखनाद हो चुका है और राजनेता अपने वोटर का ध्यान अपनी ओर करने के लिए किसी भी स्तर का बयान देने से बाज नहीं।

आते भगवन श्रीराम के अस्तित्व पर सदैव सवाल उठाये जाते हैं और यहां तक कहा जाता है की भगवन श्रीराम हैं हीं नहीं। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म की रक्षा एवं श्रीराम के होने का वैज्ञानिक सबूत कभी देने की बात भाजपा लगातार करती आ रही है। भाजपा में राम और रामायण पर विवाद है, लेकिन इंडो-शिया में श्रीराम कथा के वजूद को जीवंत रखने के लिए सरकार कार्यक्रम करती है।

ते

ता युग से ही भगवन श्रीराम के नाम की राजनीति होती आ रही है और जितनी मुंह उतनी बातें श्रीराम एवं रामायण पर की जाती हैं, क्योंकि सनातन धर्म में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है लेकिन धूलवश भी आग कूराण पर लिप्पणी कर दी तो आपकी खैर नहीं है। ऐसी मानसिकता का आधिकारक कारण क्या है? रामायण भले हीं एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ ग्रंथ है लेकिन इसके सभी पात्र आज आजाद भारत में देखने को मिल जायेगा और इसके पात्र की तुलना अपनी-अपनी सुविधानुसार करते हैं। समाजवादी नेता रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तो राम को काल्पनिक मानते हैं। मुस्लिम देश इंडो-शिया भगवन राम में आस्था रखता है तो गैर हिन्दू देश श्रीलंका ने कभी भगवन श्रीराम का होने का सबूत नहीं मांगा। आज संचारक्रांति के 21वीं सदी में पूरा विश्व हारे कृष्ण होरे राम कर रहा है, लेकिन सनातन के राष्ट्र भारत में हीं भगवन को अपनी भूमि के लिए कोई में सबूत देकर मदिर निर्माण के लिए 500 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। मुस्लिम वोट के खातिर भगवन श्रीराम और उनके जीवन पर आधारित कथा को कटघरे में खड़ा हीं नहीं किया जाता बल्कि अभद्र टिप्पणी की जाती है। मुख्यमंत्री बनने की बैचैनी या फिर नीतीश कुमार की राजनीति को धूल चढाने के लिए पहली बार नीतीश कुमार को राजद के कार्यालय के होटिंग्स में भी जगह मिली है, वह भी भगवन श्रीराम एवं कृष्ण के रूप में। वहीं दूसरी ओर राजद कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर तो रामायण को ही चुनौती दे रहे हैं। वैसे में राजद के कार्यालय में लगा बैनर मुख्यमंत्री को मूर्ख बनाने के लिए तो नहीं लगा है? दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ बिहार में महागढ़बन्धन सरकार के मुखिया हैं, लेकिन पहली बार उनका पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में लगा है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना भगवन राम और कृष्ण से की गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राक्षसराज रावण और कंस से की गई है। जब रामायण और गीता, समाज तोड़ने वाला धार्मिक ग्रंथ है तो राजद की नजरों में नीतीश कुमार ग्रंथ के अनुसार भगवन श्री राम और कृष्ण हो गए। इससे साफ हो जाता है की राम और कृष्ण का वजूद है। 2024 के लिए यह सुगुफा था, जिससे तीर के एक सिरे से भाजा पर बार तो दूसरे छोर से जदयू पर भी बदला वाला हमला है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के गैजिम्मेदाराना बयान से राजद से अधिक नुकसान नीतीश कुमार को ही होगा और साधु-संत, राजनितिक दल से लेकर साहित्यकार तक मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रामचरितमानस विवाद पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बोले की इस मुदे पर राजद को देखना चाहिए कि शिक्षा मंत्री का क्या करें, अन्यथा इससे भाजा को फायदा होगा। राम चरितमानस पर विवाद है लेकिन उसके पात्र भगवन श्री राम, राक्षस रावण, कृष्णकरण, मेघानाथ, सूर्यनखा जैसे लोगों पर अपने सुविधा अनुसार एवं राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम का उदाहरण दूसरे दल के नेताओं पर करने से बाज नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी भगवन श्री राम के वजूद होने की लड़ाई लड़कर आज सरकार में है तो दूसरे दलों में यह कहा जाना कि रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कोई कहता है कि राम का जितना वजूद था, उससे ज्यादा वजूद श्री कृष्ण का है। वैसे में दोहरी बात करने वाले लोग यह भूल चुके हैं कि भारत के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भगवन श्री राम और कृष्ण का क्या वजूद है, वह चुनाव के वक्त मुंहतोड़ जबाब देकर बूथ से आते हैं। श्रृंगी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी श्रृंगी ऋषि महाराज का कहना है कि, सर्वविदित है रामचरित मानस समाज में मर्यादा और सभी जातियों और वर्गों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों तक को साथ लेकर चलने का संदेश देने वाला जनप्रिय महाकाव्य है। ऐसे में हिन्दू सनातन धर्म की प्राणवायु रामायण को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहना अपनी ओछी सियासत का प्रदर्शन करना है। त्रिवेणी के तट पर लगे माघ मेला क्षेत्र में 285 राम कथाचाचक और भगवन राम को अपना इष्ट मानने वाले आठ हजार से अधिक वैष्णव संप्रदाय के साधु संत मौजूद हैं, जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामायण पर दिए गए विवादस्पद बयान को लेकर यहां से कोई बड़ा आंदोलन भी यह रामभक्त कर सकते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में भगवन श्री राम मंदिर का निर्माण करवाकर 400 सीट जीतने की कोशिश में लगे हैं तो वही उनको गही से उतारने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़े पदयात्रा पर निकले हैं। सलमान खुशीद ने तो चंद्रशेखर का बचाव करते हुए कहा कि इसको गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हम भगवन श्रीराम के आदर्शों पर ही उनसे प्रेरणा लेकर इस यात्रा को निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार की गही पर काबिज होने की बैचैनी में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यह दावा करते हैं की रामायण समाज में नफरत फैलाती है और अब यह राजनीतिक डुगड़गी बजा चुके हैं।



दिसंबर 2022

भारत रत्न विशेषांक**मिश्रा जी,**

दिसंबर 2022 अंक में भारत रत्न विशेषांक पढ़कर वास्तव में काफी प्रफुलित हुआ तथा लेखक सहित समस्त टीम को दिल से बधाई। इस अंक से प्रतियोगी छात्रों को सटीक जानकारी प्राप्त हो रही है। केवल सच पत्रिका का यह अंक पठनीय, संग्रहणीय है और इस प्रकार का सराहनीय प्रयास आपका संगठन निरंतर कर रहा है। सभी भारत रत्न की एकसाथ जानकारी किसी भी वक्ता को बोलने के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। ऐसे ही संग्रहणीय अंकों को पाठकों के बीच रखें।

★ संजय कुलश्रेष्ठ, आर के पुरम, नई दिल्ली

सतर्क एवं सजग**ब्रजेश जी,**

अपनी बेबाक लेखनी के लिए केवल सच सरकार एवं समाज में खास स्थान रखता है। सेना से सेवानिवृत ललन सिंह की खबर राष्ट्रहित में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी रहता है। दिसंबर 2022 अंक में भारत में बदलाव के माहौल में सतर्क एवं सजग केंद्र सरकार खबर में केंद्र सरकार के सख्त सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है का माहौल सच में बदल गया है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुरक्षित हुआ है। यह खबर सच में उल्लास उमंग से भरा है।

★ प्रदीप सक्सेना, श्याम बाजार, कोलकाता

श्रद्धा मर्डर**संपादक जी,**

दिल्ली की घटना दिल को दहला ही देती है। अभी बेटी निर्भया को इंसाक मिला तो लगा की अब दिल्ली में बेटियों को सुरक्षा मिलेगा लेकिन श्रद्धा की टुकड़ों में हत्या की खबर ने दिल्ली को फिर से दहला दिया है। दिसंबर 2022 अंक में संवाददाता गुरुमी साव की खबर मां बाप की आज्ञा का पालन नहीं करने का परिणाम श्रद्धा मर्डर ने सोचने को मजबूर कर दिया है की आखिर बड़ी घटना के लिए दिल्ली शहर ही क्यों सुरक्षित है जबकि सर्वोच्च न्यायालय एवं काबिल पुलिस का शहर है। यह खबर वर्तमान समय में युवाओं को सचेत करती दिख रही है।

★ मंजू उरांव, सेक्टर 6, बोकारो

**हमारा ई-मेल****हमारा पता है :-**

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगती तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच**राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका****द्वारा:- ब्रजेश मिश्र**

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

मालवीय जी**ब्रजेश जी,**

मैं केवल सच का नियमित पाठक हूं और इसमें प्रकाशित सभी खबरों को पढ़ा हूं। दिसंबर 2022 अंक में भारत रत्न महामना पर्डित मदन मोहन मालवीय जी के साहसिक प्रयास को पढ़ने को मिला। मालवीय जी के जीवन से जुड़ी सभी प्रमुख बिंदुओं को पढ़ा तो यह भी जानकारी प्राप्त हुई की सत्यमेव जयते के रचयिता भी यही था। किस प्रकार हिंदुस्तान में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना तथा इसकी महत्व को प्रासांगिक बनाना यह अपने आप में बड़ी बात है। यह अंक वास्तव में मिल का पत्थर है।

★ मनोज पाठक, अशोक नगर, रांची

आपूर्ति**मिश्रा जी,**

बिहार में विकास की रफ्तार सही मायने में देखा जा सकता है। गया शहर धर्म अध्यात्म के साथ व्यापार और मोक्ष के लिए खास स्थान रखता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खास पहल के कारण जहां फल्गु नदी में पानी का संकट झेलना पड़ता था वहाँ गंगाजल की आपूर्ति करवाकर लोगों का दिल जीत लिया है। राजगीर में भी गंगाजल की आपूर्ति योजना का शुभारंभ करके नालंदा जिला के लोगों को घर घर गंगाजल पहुंचाने का संकल्प पूरा किया है। मिथिलेश कुमार एवं ललन कुमार की खबर काफी जानकारी पूर्ण है।

★ संजय कुशवाहा, रमना रोड, गया

डमाडोल**संपादक जी,**

केवल सच पत्रिका बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के करतूत पर खबर नहीं लिखे यह हो ही नहीं सकता है। दिसंबर अंक में शशि रजन सिंह और राजीव शुक्ला की संयुक्त खबर तेजस्वी यादव के राजनीतिक मजबूरी के कारण स्वास्थ्य विभाग डामाडोल में विभाग के अधिकारी और मंत्री सहित नियमों की अवहेलना की सटीक जानकारी प्राप्त हुई। नियम के विरुद्ध बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रेणु कुमारी किस प्रकार अधिसूचना जारी करती हैं पढ़कर ऐसे महसूस हुआ की विभार का स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है।

★ कौशल सिन्हा, राजेंद्र नगर, रोड नं 6, पटना

अन्दर के पन्नों में**राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त निकले शिरकंडी****2024 के लिए पीएम फेस39****सुषमा बड़ाइक पर चलाई गई गोलियां....85**

RNI No.- BIHHIN/2006/18181,
समृद्ध भारत



DAVP No.- 129888
खुशहाल भारत



निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 17,

अंकुः 200,

माह:- जनवरी 2023,

मूल्यः 20/- रु

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769

8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरुण कुमार बंका

7782053204

सुरजीत तिवारी

9431222619

सच्चिदानन्द मिश्र

9934899917

ललन कुमार प्रसाद

9334107607

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

रीता सिंह 7004100454, 9308729879

उपसंपादक

अरबिन्द मिश्र 9934227532, 8603069137

प्रमुन पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय

7488696914

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरि 9905048751, 9431644829

प्रदीप कुमार सिन्हा 9472589853, 6204674225

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्द्र कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्लूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्लूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

कुमार सौरभ 7004381748, 9102366629

गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

कार्यालय संचादकाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्लूरो

पट्टा (श०) :- श्रीधर पाण्डेय 09852168763

(म०) :-

(ग्रा०) :-

बाढ़ :-

भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547

बक्सर :- विन्ध्याचल सिंह 8935909034

कैमूर :-

रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506

गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916

(ग्रा०) :-

ओरंगाबाद :-

जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939

अरबल :- संतोष कुमार मिश्र 9934248543

नालन्दा :-

नवादा :- अमित कुमार 9934706928

मुग्गे :-

लखीसराय :-

शेखपुरा :-

बेगूसराय :- निलेश कुमार 9113384406

खगड़िया :-

समर्पतीपुर :-

जमुई :- अजय कुमार 09430030594

बैशाली :-

छपर :-

सिवान :-

गोपालगंज :-

मुजफ्फरपुर :-

सीतामढ़ी :-

शिवहर :-

बेतिया :- रवि रंजन मिश्र 9801447649

बगहा :-

मोतिहारी :-

दरभंगा :-

मधुबनी :- सुरेश प्रसाद गुप्ता 9939817141

सहरसा :-

मधेपुरा :-

सुपील :-

किशनगंज :-

अररिया :-

अब्दुल कस्यूम 9934276870

पूर्णिया :-

कटिहार :-

भागलपुर, :-

(ग्रा०) :- रवि पाण्डेय 7033040570

नवगलिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवन्यू,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो- 9433567880, 9308815605

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंकरेव, द्वितीय तल, फॉर्ट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी
मो- 6203723995, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिंहि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो- 8109932505,

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
मो- 9431073769, 9955077308

e-mail:- kewalsach@gmail.com, ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांघर्ष प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

सभी पद अवैतनिक हैं।

फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्रोत)

कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

विज्ञापन का भुगतान चेक या इफाट एवं RTGS से ही मान्य होगा।

भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

A/C No. :- 0600050004768

BANK :- Punjab National Bank

IFSC Code :- PUNB0060020

PAN No. :- AAJFK0065A

झारखण्ड स्टेट ब्लूरो

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636-9631490205

उप संपादक सह प्ररेश प्रभारी

अजय कुमार 6203723995-8409103023

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्र 7654122344-7979769647

अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

संयुक्त संपादक

.....

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्र 8210023343-8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्लूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 9431732481

साहेबगंज :- अनंत मोहन यादव 9546624444

खूंटी :-

जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724

हजारीबाग :-

जामताड़ा :-

दुमका :-

देवघर :-

धनबाद :-

बोकारो :-

रामगढ़ :-

चाँडीबासा :-

कोडरमा :-

गिरीडीह :-

चतरा :- धीरज कुमार 9939149331

लातेहार :-

गोड्डा :-

गुमला :-

पलामू :-

गढ़वा :-

पाकुड़ :-

सरायकेला :-

सिमडेगा :-

लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह



प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
 'केवल सच' पत्रिका एवं 'केवल सच टाइम्स'
 राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांफेस (इंटर्क)
 पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉर्मस
 09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार



शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
 'केवल सच' पत्रिका एवं 'केवल सच टाइम्स'
 एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
 लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
 फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार चुरेका



मुख्य संरक्षक
 'केवल सच' पत्रिका एवं 'केवल सच टाइम्स'
 डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
 भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार



मुख्य संरक्षक सह निदेशक "मगध इंटरनेशनल स्कूल" टेकारी
 " केवल सच " पत्रिका एवं " केवल सच टाइम्स "
 9060148110
 sudhir4s1@gmail.com

श्री आर के झा



मुख्य संरक्षक
 'केवल सच' पत्रिका एवं 'केवल सच टाइम्स'
 EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
 08877663300

देवब्रत कुमार गणेश



मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी, 53 ठाकुरगंज विधानसभा
 " केवल सच " पत्रिका एवं " केवल सच टाइम्स "
 8986196502/9304877184
 devbarkumar15@gmail.com

बिहार राज्य प्रमंडल ब्लूरे

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मेन्द्र सिंह	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बैंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
कुणाल कुमार सिंह	9988447877, 9472213899

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा कुमार	9608084774, 9835829947

भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय केवल सच सम्मान-2022 कार्यक्रम संपन्न



● आशुतोष पाठक/पूनम जायसबाल

Dर्ष 2006 में जब केवल सच पत्रिका की नीव रखी गई थी, तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आज यह संस्था अपने 17 वर्ष को पूरे करते हुए 18वें वर्ष में प्रवेश करके युवा पत्रकारों की सैकड़ों टोली बिहार प्रदेश के जिला और प्रखण्ड तक ही नहीं वरन् देश के अन्य राज्यों में भी अपना परचम फैलाने में कामयाब होंगे। और आज का वक्त इन 17 वर्षों के संघर्ष और त्याग का ही परिणाम है कि केवल सच हिन्दी मासिक पत्रिका, राष्ट्रीय मुकाम पर कदम आगे बढ़ाने में कामयाब होते दिख रही है। इन तमाम उपलब्धियों का श्रेय पत्रिका के संपादक सह संस्थापक श्री ब्रजेश मिश्र जी के कुशल नेतृत्व को दिया जा सकता है। क्योंकि उनके मार्गदर्शन पर आज सैकड़ों पत्रकार बंधु केवल सच से जुड़कर समाज, राष्ट्र में अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक युग, अर्थ युग के साथ चलने को मजबूर है। बावजूद इसके केवल सच से जुड़े वह तमाम पत्रकार केवल सच को बुलदियों तक पहुंचाने में जी-जान से

जुटे रहते हैं। श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले केवल सच राष्ट्रीय पत्रिका के साथ ही समय के साथ नये-नये और भी संगठन को शुरू किया गया। जिनमें केवल सच टाइम्स द्वीपांशीय पत्रिका, केवल सच लाइब डॉट इन पोर्टल चैनल और केवल सच न्यूज यूट्यूब चैनल इनमें शामिल हैं।

वितरण करने के साथ-साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी अपनी महत्ती भूमिका को अदा करते आया है। वही बताते चले कि श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट और केवल सच समूह के द्वारा वर्ष में तीन बड़े कार्यक्रम पटना, रांची और दिल्ली में आयोजित किया जाता रहा है और समाज में अपना योगदान देने वाले लोगों को केवल सच सम्मान से सम्मानित भी किया जाता रहा है। बीते वर्ष जून 2022 की बात करें तो राजधानी पटना में चिकित्सा जगत में सर्जरी के जनक कहे जाने वाले महर्षी सुश्रुत पर कार्यक्रम किया गया। उसके बाद सिसम्बर 2022 में रांची में देश की आजादी में प्रमुखता से आन्दोलन का आगाज करने वाले तिलका माझी पर कार्यक्रम किया गया और दिसम्बर 2022 में काशी विश्वविद्यालय के जनक और प्रखर अधिवक्ता भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय केवल सच सम्मान-2022 कार्यक्रम को किया गया।

सनद् रहे कि दिनांक 25 दिसम्बर 2022 को केवल सच समूह एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के द्वारा 'भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय के बल सच सम्मान-2022' कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हाँल



गौरतलब हो कि

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के साथ केवल सच सामाजिक संस्थान सामाजिक कार्यों में भी बड़-चाढ़कर हिस्सा लेता रहा है, जिनमें गरीब बच्चों को मुफ्त कॉर्पी-किताब का वितरण करके, दिव्यांगजनों को मुफ्त ट्राइ साइकिल का वितरण करके, गरीब असहाय लोगों के बीच केवल



में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में केवल सच राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय एवं भारत के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की जयंती पर तथा भारत के सम्मान में चार चांद लगाने वाले वह 48 विभूति जिन्होंने खेल, फिल्म, विज्ञान, सहित्य, समाज सेवा सहित कई क्षेत्रों में अपनी महत्ती भूमिका अदा की और जिन्हें भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया है, उनपर 'भारत रत्न विशेषांक' प्रकाशित किया है।

कार्यक्रम की शुरूआत सर्वप्रथम भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा पुष्ट अर्पित किया गया। उसके बाद दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के बाद 'भारत रत्न विशेषांक' का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में,

संजय दुवेदी,

(निदेशक, आई आई एम सी, नई दिल्ली),

समीर कुमार महासेठ

(उद्योग मंत्री, बिहार सरकार),

श्री सुधांशु त्रिवेदी

(सासद),

डॉ. आशीष कंधवे

(संपादक, गगनांचल, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार),

श्री कपिल मिश्र

(पूर्व मंत्री, दिल्ली),



हामना मदन जोहन मालवीय



सच सम्मान - 2022

मात्रांक :- 25 दिसंबर 2022

सच विशेषांक का विमोचन

आयोजक:-



कार्यक्रम



हरि शंकर सिंह

(कार्यकारी अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन, दिल्ली),

श्री संजय मयूरख

(राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, भाजपा)

श्री ब्रजेश मिश्र

(संपादक सह संस्थापक, केवल सच) की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केवल सच के संपादक सह संस्थापक ब्रजेश मिश्र ने किया। उक्त कार्यक्रम में 'केवल सच समूह एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट' के द्वारा समाज में उत्कृष्ट योगदान दे रहे गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें :-

डॉ सुनील कुमार (चिकित्सक),

डॉ सुभाष चंद्र (चिकित्सक),

संजीव कुमार मिश्रा (कानूनी सेवा),

डॉ सतीष चंद्र मिश्रा (कानूनी सेवा),

डॉ क्षमा द्विवेदी (चित्रकार),

रोहित कुमार उर्फ सोनू सिंह (समाजसेवी),

विजय कुमार मिश्रा (शिक्षाविद्),

निरज पाठक (सामाजिक कार्यकर्ता),

बबन कुमार मिश्रा (समाजिक कार्यकर्ता),

अजीत शुक्ला (कानूनी सेवा),

उमाशंकर सिंह (शिक्षा सेवा),

ब्रजेश सहाय (पत्रकारिता),

आनंद कुमार केड़िया (प्रधान आयुक्त, आयकर सेवा),

गोपाल केड़िया (सी.ए.),

विष्णु कुमार सुल्तानिया (सी.ए.),

रागिनी तिवारी (समाजसेवा) सहित केवल सच पत्रिका के विभिन्न राज्यों से



सुधांशु त्रिवेदी

आये पत्रकार शामिल हैं।

‘भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय केवल सच सम्मान-2022’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सुधांशु त्रिवेदी ने मदन मोहन मालवीय जी एवं अटल बिहारी बाजपेयी जी पर चर्चा करते हुए कहा कि मालवीय जी ने हन्दू विश्वविद्यालय की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आगे त्रिवेदी जी ने कहा कि इंडोनेशिया में 12 फुट की माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है और वहां पर भी पहले ज्ञान की देवी की पूजा होती है। आगे उन्होंने कहा कि मॉर्डन साइंस एवं टेक्नोलॉजी में भारत की अग्रनी भूमिका है, जिसमें काशी विश्वविद्यालय का योगदान बहुत है। केवल सच के बारे में क्या कहें, यहां तो भीड़ बिहार से भरी परी है, जिसके प्राचीनी की बातें अनगिनत हैं। ‘गिनत गिनत थक जइहें अंगुली हमार, यहां ह महापुरुष हजार, यही ह बिहार-यही ह बिहार।’



कपिल मिश्रा

आगे उन्होंने कहा कि संस्कार, शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्रजेश जी का प्रयास सार्थक दिख रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित कर रहे अगले अतिथि श्री संजय द्विवेदी ने कहा कि आज के दिन दो महापुरुषों को याद करने का दिन है। अटल जी एवं मालवीय जी ने पत्रकारिता में काफी योगदान दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं ब्रजेश जी का, जिन्होंने यह कार्यक्रम को कराकर महापुरुषों के योगदान का महत्व बढ़ाया।

पूर्व मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ब्रजेश जी आपके कलम में सरस्वती तो हैं ही आपकी वाणी में भी सरस्वती हैं। इस विशेषांक को देखा और पढ़ा तो पता चला कि ‘सत्यमेव जयते’ अगर किसी की देन है तो वह मदन मोहन मालवीय जी की है। वही मालवीय जी वह थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों के पक्ष में केश लड़ते थे। चौरी चौरा इसका उदाहरण है। आगे कपिल मिश्रा ने कहा कि आज



संजय द्विवेदी

मालवीय जी एवं अटल जी की जयंती के साथ ही तुलसी जयंती भी है। पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि केवल सच पत्रिका का 17 वर्ष बिल्कुल संघर्ष से भरा होगा, क्योंकि मेरे पिता ने भी पत्रिका को चलाया है और जिसमें अपना खून, पसीना बहाना पड़ता है। ब्रजेश जी से ज्यादा उनके परिवार वालों को त्याग करना पड़ता होगा।

श्री आशीष कंधवे ने कहा कि ब्रजेश जी की निष्ठा को सलाम है। आज शिक्षा ज्योति दिवस है और आज हम उनके दो ज्योति मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी बाजपेयी जी का दिवस मना रहे हैं। मालवीय जी के बारे में बताते हुए कंधवे जी ने कहा कि मालवीय जी का कहना था कि ‘मुझे इत्र का गंध पसंद नहीं है, मुझे हिन्दुत्व का गंध पसंद है।’ यशस्वी पीएम मोदी जी जोर दे रहे हैं कि कैसे युवाओं को जोर कर रखे और उस समय मालवीय जी भी यह करते थे। हरकी पौड़ी पर गंगा आरती की



आशीष कंधवे



हरिशंकर सिंह



संजय मधूख



शुरूआत भी महामना मालवीय जी की ही देन है।

लोकप्रिय युवा नेता एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी माँ कहा करती थी कि 'तुझे सूरज कहूँ या चंदा....., मेरा नाम करेगा रौशन मेरा राज दुलारा', तो हम सब

आ रहे हैं। विश्व में जिस तरह मदन मोहन मालवीय जी की ख्याति हुई, उसी तरह केवल सच और ब्रजेश मिश्र जी की होती रहे, यही मेरी शुभकामना है।

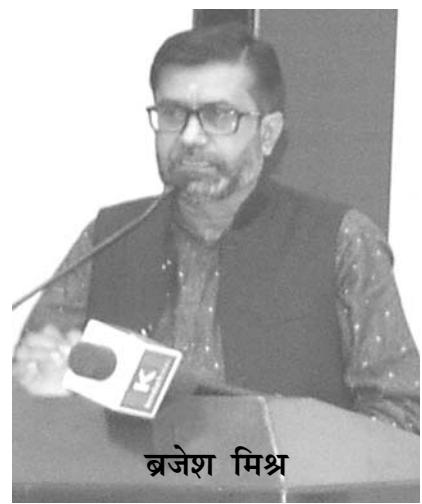
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। मेरे पिता भी बीएचयू के छात्र रहे हैं। मैं उनसे पूछता था कि बीएचयू के अच्छे प्रोफेसर कौसे होते हैं। वह बताते थे कि बिहार में आधे से ज्यादा मंत्री बीएचयू के प्रोफेसर हुए। सोचिए की बीएचयू में पढ़ने वालों की क्या सोच रही होगी। अभी और नये अच्छे दिन लाने के प्रयास में केवल सच पत्रिका किस कष्ट से निकालते होंगे यह हमें समझना होगा। अपेक्षा है इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम बिहार से दिल्ली आये हैं।

हरि शंकर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा की मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी बाजपेयी जी की जयंती पर केवल सच पत्रिका आज जो कार्यक्रम करा रही है, इसके लिए मैं ब्रजेश जी को धन्यवाद दूंगा। देश की आजारी के आंदोलन में मालवीय जी का योगदान एवं प्रधानमंत्री के पद पर भारत में सड़क योजना, पोखरन और कई ऐसे कार्य करके अटल जी ने देश का सम्मान बढ़ाया और आज इनकी जयंती पर मैं यहां उपस्थित होकर खुद को गौरवान्ति महसूस कर रहा हूँ।



का राज दुलारा ब्रजेश जी ने तिनका-तिनका एक करके केवल सच को यहां तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि किसी भी सभा से निकलना तो बटोर कर सबकुछ निकलना और मैं यहां उनकी बातों को गौर कर रहा हूँ। ब्रजेश जी के बारे में बता दूँ कि वह आज ही नहीं पहले से भी मालवीय जी की जयंती मनाते

अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए मंच की अध्यक्षता कर रहे केवल सच के संपादक सह संस्थापक ब्रजेश जी ने कहा कि केवल सच पत्रिका एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट का प्रयास यही रहता है कि आम जनमानस के बीच वह संदेश जाये, जिनसे कई लोग अनभिज्ञ



है और मालवीय जी तथा अटल जी के साथ 48 विभूतियों को मिले भारत रत्न सम्मान को लेकर जो भारत रत्न विशेषांक का विमोचन हुआ, उसे पढ़कर पाठक जरूर खुश होंगे। वही केवल सच समूह एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट हर वर्ष पटना, रांची और दिल्ली में समाज को अच्छे संदेश देने के साथ कार्यक्रम कराती रही है। ●



ब्रह्मद्वारा विकास में जाहफ निगम

घोटालो के आगे घुटना टेक दिये सुशासन बाबू!

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

सु

शासन की बात कहने वाले नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचारियों ने अंदर पैर जमा लिया है। ऐसे तो नगर निगम पहले से ही अपने भ्रष्ट तरीकों के लिए मशहूर है लेकिन जब से पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेष कुमार पाराशर बने हैं तब से नगर निगम भ्रष्टाचार में मीठी कटारी बन गई है। अनिमेष कुमार पाराशर के आयुक्त बनते ही कई ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया गया है और उनसे अधिक कमीशन की मांग किया जाने लगा है। ईमानदारी का चोला पढ़ने आयुक्त महोदय बरसाती पहनकर भ्रष्टाचार में स्नान करने लगे हैं अगर आपकी संस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। आज नगर निगम में अवैध होर्डिंग, अवैध फुटपाथ दुकान से नगर निगम के अधिकारियों का महीना फिक्स है, इसके जिम्मेदार कौन है? साफ-सफाई से लेकर सड़क बनवाने तक में नगर निगम का कमीशन फिक्स है यहाँ तक की मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र भी बिना

पैसों का निर्गत नहीं हो पा रहा है।

पटना नगर निगम उन दिनों सुर्खियों में था जब बिहार के उपमुख्यमंत्री रहे श्री सुशील कुमार मोदी हाफ पेट पहनकर अपने परिवार के साथ सूट केश लिए फुटपाथ पर गाड़ी का इंतजार करते देखे गए। यह अंदाज उन दिनों किसी फिल्मी दृश्य को दर्शा रहा था, तब श्री मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर पंद्रह वर्षों तक काबिज थे, अन्य विभाग के साथ बदतर स्यूनिसपल्टी को सुधारने के लिए नगर विकास विभाग का जिम्मा भी दिया गया, वही खान एवं भूतल विभाग भी इनके जिम्मे रहा। पब्लिक से जुड़े दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं जहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत-आवेदन पहुंचने से अधिकारी पदाधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उपर से कोई कार्रवाई नहीं होती, आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ कितने गहराइयों तक असर डाल रखा है। स्थिति यह है नगर निगम में घोटाले का अम्बार लगा है, जहाँ के नगर विकास में बाधक ठोकेदार-अधिकारी तो है ही कुछ हद तक आम पब्लिक भी जिम्मेदार हैं जो यह सब देखते हुये मौन रहते हैं, समय आने पर हमें ऐसे स्थानीय जनप्रतिनिधि की जड़ को

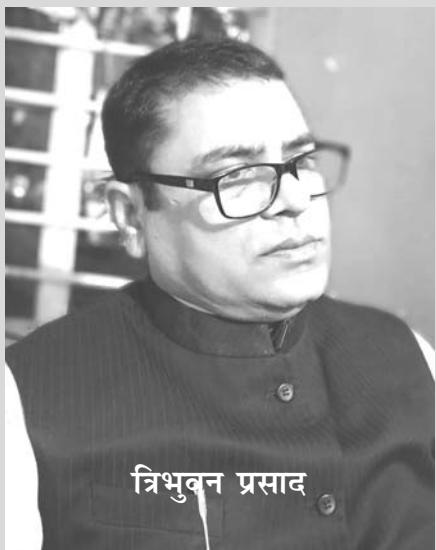
कबारना होगा।

पटना अब धीरे धीरे मेट्रो की तरफ बढ़ रहा है, नगरवासियों का रहने-सहने फुटपाथ पर चाइनीज, चिकेन खाने की आदत पड़ रहा है, यूथ को जो पसंद है वह नगर निगम के पाले बहुत सारे ऑप्शन है, जिसे विकसित करके पटना को ग्रीन एवं क्लीन करने के साथ-साथ स्टेट थैंडर और वेडिंग जौन को बेहतर किया जा सकता है। इन सबके पीछे सिर्फ मंशा रखने से नहीं हो सकता एक्शन में आना होगा, किन्तु सवाल फिर से खड़ा हो जाता है की आखिर यह सब तभी दिखेगा, जब तांडवकारी अधियंता-अधिकारी को दर्दित किया जाये।

विषय प्रवेश :- जो हम नगर निगम में पानी-पानी और ड्रेनेज सिस्टम पर ले जाना चाहते थे, तब पटना के पॉस इलाके राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, लंगर टोली, बहादुरपुर, गर्दनीबाग, पोस्टल पार्क, चांदमारी रोड, इंदिरा नगर, अशोक नगर, रामकृष्ण नगर, पाटलिपुत्र, राजीव नगर, दीघा सहित तमाम इलाके में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। वर्ष 2019 पटना नगर निगम के लिए बेहतर करने के लिए एक प्राकृतिक आईना था, जिससे सबक

मोटर पम्प खरीदनी में करोड़ों रुपये कि लूट दस लाख के मोटर पम्प, जिसे तीस लाख में लिया गया

त्रिभुवन प्रसाद ने कहा कि साक्ष्य को प्रमाण कि क्या आवश्यकता! 2019 कि विभीषका को देखते हुये पाटलिपुत्र अंचल सहित नगर निगम में जल जमाव कि उराही के लिए 26 HP, 33 HP, 83 HP का मशीन कि आपूर्ति हेतु निविदा आमत्रित किया गया निविदा पूर्व एजेंडा सेट कर Adam नामक एजेंसी से कॉस्मिक कम्पनी का मोटर पम्प लिया गया, कुछ और भी एजेंसी इसमें शामिल है जिनसे उपरकण कि खरीदारी से पूर्व डोनेशन डिले किया गया है, जिसकी शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल नगर निगम, पाटलिपुत्र से किया गया था किन्तु आजतक इसकी



त्रिभुवन प्रसाद

जांच नहीं किया गया क्योंकि वे खुद इस खेल में शामिल हैं वही स्थिति बांकीपुर, फूलवारी, दानापुर सहित विहार के नगर पालिका में 60 प्रतिशत अधिक दामों पर मशीनों कि आपूर्ति हेतु टेंडर प्राप्त किये गये जो कि प्रायोजित रूप से सेट अजेंडा के तहत ऐसा कृत किया गया जिस बात जानकारी विभाग को दिया गया है। आपूर्तिकर्ता सतीश राय, आरा निवासी

तथा संजीव कुमार जिनका शॉप बिस्कोमान पटना के चौगाहे से पहले अवस्थित दुकान है। उनकी बात नगर निगम में मानव बल आपूर्ति कर्ता गुड ईयर एजेंसी के सफाई कर्मी राहुल वर्मा के मोबाइल से कि गई बातचीत है जिसमें डीलर सतीश राय नगर निगम में मोटर पम्प मशीनों स्वयं के आपूर्ति कर्ता है जो राहुल वर्मा सफाई कर्मी से इस बात का खुलासा करते नजर आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए मशीन चाहिए या नगर निगम के लिए चुकी नगर निगम के अलग से दाम फिक्स है जिसमें EO, CO को डोनेशन देना पड़ता है। आगे बातचीत में उसने कहा है कि 26 HP मशीन का दस बारह लाख रुपये में मिल जाएगा वही निगम में देना है तो तीस लाख का कोटेशन बनाने होंगे, 33 HP का दाम बाहर में बारह लाख रुपये है जबकि निगम के 33 लाख, 83 HP पम्प मशीन को 28 लाख रुपये में आपको दे दिया जायेगा जबकि निगम को चाहिए तो उसे 55 लाख रुपये का कोटेशन देना होगा। बातचीत का ऑडियो क्लिप नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को लिखित आवेदन के साथ कार्रवाई के लिए दिया गया है। उक्त मामले कि गंभीरता को देखते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्य सचिव, बिहार सरकार से विभाग के प्रधान सचिव को जांच एवं कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया है। श्री यादव ने कहा कि मामले में अधिकाई राशि कि रिकवरी किये जाने के साथ दोषियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। आपूर्तिकर्ता ने इस बात पर जोड़

देते हुये कहा है कि EO, CO के आलावे बहुत जगह डोनेशन देना पड़ता है जिस बात को हम मोबाइल पर नहीं बोल सकते हैं। उसने पटना नगर निगम के आलावे कई दूसरे जिले में आपूर्ति करने कि बाते कि हैं जो जांच का विषय है। श्री यादव ने कहा कि एक प्रकार से कंपनी के अधिकृत डीलर कि काली कमाई और लूटपाटा में साठगांठ कि जांच अलग से निगरानी विभाग को सौंपना चाहिए जिसको भी कार्रवाई हेतु लिखित आवेदन दिया गया है।

बिना कार्य किये हजारों सफाई कर्मी के नाम पर हर महीने कर लिया गया करोड़ों रुपये कि फर्जी निकासी मानव बल आपूर्ति कर्ता एजेंसी गुड ईयर, इम्प्रैशन, एवरेस्ट जो तीनों एजेंसी के माध्यम से नगर निगम में पिछले तीन वर्षों के दरम्यान 1000 सफाई मजदूरों के फर्जी उपस्थित हाजिरी बनवा कर करोड़ों रुपये कि सरकारी राशि कि निकासी कर घोटाला कर लिया गया। इस



आनंद किशोर

बात की खुलासा तब हुआ जब वारिश कि पानी से जलमग्न पटना कि सफाई के लिए हर वार्ड में अधिक मजदूर लगाए गए किन्तु कार्य नहीं होते देख इस बात कि शोर नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी में उठा, आरोप कि जांच वर्तमान नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के द्वारा अंचलों कार्यालय के निरक्षण के दरम्यान सफाई कर्मियों कि उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया गया, तब 1000 कर्मी महीनों से गायब पाये गए। दरअसल यह अनुपस्थित पिछले तीन वर्षों से है जिनके नाम पर फर्जी राशि की उठाव कर घोटाले किये गए जिसमें करोड़ों रुपये लुटा गया। इस प्रकरण का खुलासा करते हुये नगर आयुक्त ने नगर निगम में बायोमीट्रिक सिस्टम को लगा कर हाजिरी बनाने कि अनिवार्य किये और कहा गया कि अनुपस्थित सफाई मजदूरों को दुबारा काम पर नहीं रखा जाएगा साथ ही साथ इस मामले कि तह तक जाकर कार्रवाई कि जायेगी किन्तु अब मामला और प्रकरण सब ठंडे बस्ते में चला गया। श्री यादव ने बताया कि उक्त प्रकरण में क्या कार्रवाई कि गई इसके लिए भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया गया है। उन्होंने कहा इस प्रकरण में पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल किया गया है जिसका उद्भेदन किया जाएगा।

भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलना केवल सच का दायित्व है। केवल सच अगले अंक में नगर निगम आयुक्त अनिमेष कुमार पाराशर के नगर निगम सहित अन्य पदस्थापित जगहों में किए गए भ्रष्टाचार की पोल भी परत दर परत खोलेगा।

लेकर ड्रेनेज सिस्टम के साथ नागरिक सुविधा के बेहतरी के लिए अच्छा किये जाने का एक सुनहरा मौका मिला जिसमें इंजीयरिंग और तकनीकी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान किया जा सके। बिहार के सुशासन बाबू के सामने यह सब हुआ जिनके माध्यम से नगर निगम को क्या चाहिए, संज्ञान में आया, नली-गली-सड़क पीसीसी को ठीक-ठाक करने के साथ सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम को रिच स्टीमेट बनाकर और बढ़िया से चकाचक किये जाने के लिए पटना को बजट का विस्तार किया गया। मेट्रो पर चढ़ा कर पटना को क्लीन और ग्रीन दिखाया गया, लेकिन आज स्थिति यह है भ्रष्टाचार अपनी ताकत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बानगी है कि सड़क निर्माण में आइटम वाइज मटेरियल को गायब कर ढक दिया जा रहा है।

◆ आइटम वाइज मटेरियल को गायब कराने में महारथ हासिल रखते हैं अभियंता :- उक्त प्रसिद्ध है कि जिसके सिर पर उपर वाले के हाथ हो उसे भला कौन बिगड़ सकता है। पाटलिपुत्र अंचल, नगर निगम, पटना के कार्यपालक पदाधिकारी कि जड़े विभाग के उच्चपदस्थ अधिकारी तक फैला है, जिस कारण लम्बे समय से पद पर रहते नगर निगम को स्वच्छ करने जुटी है, जहाँ सरकारी कार्यों में ठेकेदार अपने हाथ क्लीन कर करोड़पति बन गए। कार्यों का निरीक्षण कार्यालय पर जाकर नहीं कि गई, इस बजह से अभियंता घोटाला करने में मस्त है, जिसकी काली कमाई से धन अर्जित किया गया है।

◆ शिकायतकर्ता को घर पर बुलडोजर चलाने को दी गई नोटिस :- सामिजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टविस्ट श्री त्रिभुवन प्रसाद



यादव द्वारा योजना में करप्सन के खात्मे को लेकर पिछले तीन वर्षों से लगातार संघर्ष किया जा रहा है तब से अबतक शिकायतों के अम्बार लगा है, साक्ष्य के साथ प्रमाण भी प्रस्तुत किये गए हैं किन्तु आजतक निगम कर्मियों, अभियंता, कार्यपालक पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर उल्टे शिकायत कर्ता के छोटी सी मकान जो आज से बत्तीस साल पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में रहते निर्मित मकान के नक्शा का बहाना बनाकर बुलडोजर चलाने कि नोटिस थमा दिया गया और पीछे से सदेश दिलवाया गया कि नगर निगम के कार्य में बाधा नहीं बनिये, उन्होंने कहा कि दरअसल यह बाधा निगम के कार्य में नहीं बल्कि लुटेरे अभियंता-पदाधिकारी-ठीकेदार के द्वारा किये जा लूट में बाधा है जिससे वे परेशान हैं।

श्री यादव ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल नगर निगम को बेहतर करने कि है जो कागजी कार्रवाई और दिये जा रहे अनुदान से स्पष्ट झलकता है जिस कार्य को एक बार प्राक्कलन के मुताबिक बनवा दिये जाय वह कम से कम पचास वर्षों तक कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि सड़क को पीसीसी करने से पहले 6 इंच मोटे GSB डाल कर प्रेशर मशीन चलाने के पश्चात 8 इंच कि ढलाई पीसीसी करना है जिस कार्य को एक बार करने से गली कि सड़के कमसे कम पचास वर्षों तक

चमकता रहेगा इसी मंशा और मिशन मूड में सरकार ने फैफिंग किया है। आरसीसी नालों के निर्माण में ISI मार्क का मोटे एम.एम का सरिया देना है, जिसपर सीमेंटेड पीसीसी का क्या कहना। वही भू-गर्भ नालों के निर्माण में पाईप विस्तारीकरण से पूर्व एक नम्बर का ईट सोलिंग कर चार इंच का पीसीसी कार्य करने का प्राक्कलन निगम क्षेत्र में लागू है किन्तु इन दोनों आइटम को लूट लिया गया है जिसकी कभी भी तकनीकी विशिष्टता रखने वाले अभियंता अधिकारी से जाँच करवाई जा सकती है जिसकी भी शिकायत विभाग में कि गई है। इस खेल में पिछले पांच वर्षों के दरम्यान हर वार्ड को कमसे कम 60 करोड़ रुपये से अधिक दिया गया है वही अन्य योजना अलग से है। उन्होंने कहा कि आशर्च्य तब हुआ जब गुलजार बाग तकनीकी लैब से मटेरियल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र पीसीसी सड़क निर्माण से पूर्व जारी कर दिया गया वह क्यूबिक टेस्ट में अवबल दर्जे का सर्टिफिकेट दिया गया जिस खेल से कार्य करने वाले एजेंसी/ठेकेदार को भुगतान जल्द हो सके तथा निगम से किये गये एग्रीमेंट को समस्या दिखाया जा सके जबकि सच्चाई इससे परे है। ऐसे जाँच एजेंसी पर सरकार को ध्यान रखना होगा, कार्रवाई के साथ क्यूब टेस्टिंग को क्रॉस टेस्ट से जाँच करवाना अतिआवश्यक है। ●



अनिमेश कुमार परासर

घोटलों का बादशाह निकला

बिहार स्पन्दन विभाग

नवादा में पत्थर माफियाओं ने सरकार के राजस्व को लगाया करोड़ों रूपये का चुना, नीतीश कुमार मौन?

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

प्र जातंत्र में सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी होता है सत्ता का परिवर्तन नहीं होने से अधिकारी भ्रष्ट होते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट प्राप्त हो जाती है। नीतीश सरकार में यह विभाग पहले भाजपा के मत्रियों के पास था लेकिन आजकल राजद के पास है, राजद के वरिष्ठ नेता रामानंद यादव इसके विभागीय मंत्री हैं। इस विभाग को भ्रष्टाचार का पुरोधा भी कहा जाता है कल भी यह विभाग भ्रष्टाचारियों का चरागाह था और आज भी कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। बिहार में उद्योग धंधों का अभाव है, नौकरी पेशा का आभाव है लेकिन जो भी बचा हुआ है वह भ्रष्टाचार को भेट चढ़ता ही जा रहा है। बालू और पत्थर के खेल में बड़े-बड़े सफेदपेश शामिल हैं जो सभी दलों के उच्च पद पर विराजमान हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी, कहने को सुशासन, सुनने में सुशासन अच्छा लगता है, कानों को कुछ देर के लिए राहत और सुकून जरूर महसूस होती है किन्तु ऐसा जो बाहर दिख रहा है उसे अंदर तक दिखे यह बड़ी बात होंगी।

आपके अधिकारी अंदर तहखाने में खेल कर रहे हैं जो करोड़ों रूपये निगलने वाले पत्थर पट्टाधारी मनीष कुमार से मिलकर पिछले सात वर्ष फाइल को दबा कर बैठे हुये हैं जिसकी शिकायत खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव से कि गई थी। शिकायत कर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि पट्टाधारी मनीष कुमार द्वारा विभाग से पांच वर्षों के लिये गए डेंड एकड़ रकबा का बंदोबस्ती 24 लाख रूपये में किया गया था जो एकरानामा के अनुसार प्रति वर्ष पांच किश्तों में 4.80 (चार लाख अस्सी हजार) रूपये जमा करना था किन्तु समय से कभी किस्त जमा नहीं किया गया। खनन का उत्खनन कर बंदोबस्थारी द्वारा अपने हाइवा ट्रक से अपने परिवार के करेक्सर मशीन पर बेचा गया जिसकी क्षमता 450 घन फिट था जिसको 300 घन फिट का चलान काटकर क्रेता को दिया गया जबकि हाइवा पर 450 घन फिट पत्थर लोड करके बेचा गया यानी प्रति हाइवा 150 घन फिट कि चोरी कि गई बाबजूद जिला खनन कार्यालय को रिटर्न के रूप में 100 फिट घन दर्शाया गया। पांच वर्षों के दरम्यान हर दिन एक ही परिवहन चलान पर कई ट्रिप गाड़ी को चलाया गया तथा विशुद्ध रूप से प्रति ट्रक/हाइवा

350 घन फिट पत्थर चोरी कर, सरकार के खजाने को लगभग पांच वर्षों में पांच करोड़ रूपये से ज्यादा का कर टैक्स कि चोरी कि गयी। विभागीय आदेश के जांचोपरांत बन्दोबस्थारी से पेनल्टी एवं कर टैक्स कि चोरी के आरोप सत्य पाया गया जिसपर सरकार के अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना जापक 2159/एम, दिनांक-18/06/2015 के निदेश पर सहायक निदेशक, खान जिला नवादा के द्वारा वसूली हेतु पत्र डिमांड पत्र जारी किया गया, एक सप्ताह के अंदर ठेकेदार से 68,21,091/- (अरसठ लाख इक्कीस हजार एकानवे रूपये) कि राशि कि वसूली के साथ-साथ ऐसा कृत करने वाले नवादा सहित बिहार के अन्य जिलों से प्रतिवेदन कि मांग कि गई जिसमें घोटाला करने का अंदेशा है। सरकार के उप सचिव श्री रमेश प्रसाद रंजन, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना के कार्यालय आदेश पत्र में स्पष्ट रूप से सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक -सह- सभी सक्षम पदाधिकारी को अपने जिला अंतर्गत पूर्व तथा वर्तमान में धारित सभी खनन पट्टों के बाबत नीलामी राशि से अधिक प्रेषित खनिज कि मात्रा पर अतिरिक्त भुगतेय स्वामित्व

भ्रष्टाचार

निवेदित

पदाका. प्र०-२ द्वारा खनन(स्टॉ)-३३/१५-
प्रेषक.

विभाग सरकार

खान एवं भूत्व विभाग

१४५ - दिनांक-

रमेश प्रसाद रंजन,

सरकार के अपर सचिव।

सेता में

सभी सामाजिक निवेदक

सभी खणिज विकास पदाधिकारी,

सभी लाग निवेदक-सह-सहाय विकास पदाधिकारी,

आपके जिलान्तरी पूर्व तथा वर्तमान में घारित सभी खनन पटों के बावत
नीलामी राशि से अतिरिक्त खणिज की मात्रा पर अतिरिक्त भुगतान
स्वामित्व की वसूली करने के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध में सूचित करना है कि नवादा जिला में घारित एक खनन पटो से संबंधित प्रशाद पत्र के आलक में उपनिवेदक, मुंगेर अंचल, एवं उत्तरनिवेदक, मगध अंचल, गया द्वारा की गई जीव के दीरान पाया गया कि वहाँ पटेहारी द्वारा सम्पूर्ण नीलामी राशि का भुगतान किया गया है तथां उन्होंने द्वारा प्रेषित पत्र के दोस्रे स्थानित्व की गणना करने पर पाया गया कि पटेहारी के विलद अतिरिक्त स्वामित्व के सबध में एक बहुत बड़ी राशि (68,84,091/- रुपये) बढ़ाया है, जिसकी वसूली करने हेतु सहायक निवेदक, नवादा को विभागीय पत्रांक-2104/एम, पटना, दिनांक-15.06.2015 द्वारा निवेदित किया गया है। ऐसे मामले अन्य जिलों में भी पाये जाने वाली संभावना है।

अतः निवेद दिया जाता है कि आप अपने जिलान्तरी सभी पूर्व एवं वर्तमान में घारित खनन पटों की पूरी समीक्षा करते हुए उक्त खनन पटों से प्रेषित खणिज की मात्रा पर देय स्वामित्व की गणना कर यह सुनिश्चित कर ले कि कोई अतिरिक्त स्वामित्व पटेहारी द्वारा भुगतान है अथवा नहीं। यदि प्रेषण के आवाह पर अतिरिक्त स्वामित्व का भी बढ़ाया है, तो उसकी वसूली संबंधित पटेहारी से करने हेतु नियमनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में जीवांपत्र यह पाया जाता है कि पटेहारी द्वारा देय अतिरिक्त स्वामित्व की वसूली हेतु आपके स्वर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी।

विभागीय जारी

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक- २१५९ /एम, पटना, दिनांक- १८/६/१५

प्रतिलिपि- सभी उपनिवेदक, खान एवं भूत्व को शूद्धीकृत एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापक- २१५९ /एम, पटना, दिनांक- १८/६/१५

प्रतिलिपि- सभी समाजीको शूद्धीकृत एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

कि वसूली करने का निवेद प्राप्त होने के बाबूजूद आजतक तक जांच प्रतिवेदन मे किये गये घोटाले कि फाइल को दबा दिया गया जिसमें अधिकारी कि मिलीभगत एवं फाइल पैण्डिंग के पीछे करोड़े रुपये का लेनदेन किया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता-सह-आरटीआई एक्टिविस्ट श्री त्रिभुवन प्रसाद यादव ने पत्थर पट्टा घोटाले पर कहा कि माफियाओं द्वारा खान एवं भूत्व विभाग का संचालन किया जाता है, जिस घोटाले कि सूचना विभाग को दिया जाता रहा है वहाँ से फाइल को ही गायब कर दिया जाता है। वर्षों-वर्ष तक फाइल को पैण्डिंग रहने के कारण तथा नहीं देखने से दीमक अपना काम कर जाता है, फाइल रहित सचिका चाटकर पनो को सफाया कर देता है बाकि बचा-खुचा असर बाबू पूरा कर देते हैं। श्री त्रिभुवन ने कहा कि पिछले छः महीने से शेखपुरा जिला खनन कार्यालय मे वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2013 तक पत्थर पट्टा घोटाले की ऑडिट वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा किन्तु अबतक ऑडिट का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है जिस मामले मे 100 करोड़ रुपये राजस्व कर (जं.) की चोरी किया गया है, जिसकी सूचना सरकार लगातार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा की वर्ष 2017 मे ही

वित्त विभाग बिहार, पटना से ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया था इस मामले मे निवेद पत्र भी जारी हुआ, अधिकारी को ऑडिट कर प्रतिवेदन का आदेश भी प्राप्त हुआ किन्तु बीच मे अचानक फाइल सचिवालय की गलियारे मे हवा खाने लगा जो अब पुनः लम्ब संघर्ष के



त्रिभुवन प्रसाद

Certificate of Public Demand
of the Office of the Collector (Name of District)

Number of Certificate	Name and address of Certificate holder	Name and address of debtor	Amount of public demand/Further part including interest, if any, and date on which such is to be paid under public demand section 3 and section 5, add. and date on which this certificate is signed, and period for which such demand is due.
सरकार के अपर सचिव	सरकार के अपर सचिव	सरकार के अपर सचिव	68,84,091/- (रुपये सixty eight thousand four hundred and nine rupees only)

I hereby certify that the above mentioned sum of Rs.

from the above named.

(If the certificate is signed on regulation suit under section 5, add.)

I further certify that the above-mentioned sum of Rs.

is justly

receivable and that its recover by suit is not barred by law.

Dated this

day of

20

पश्चात् ऑडिट का कार्य किया जा रहा है जिसपर नये सिरे से आवेश प्राप्त है। उपरोक्त मामले जैसे मिलते-जुलते कांड जिला खनन कार्यालय पटना मे किया गया जो वित्तीय वर्ष 2010 से 2012 के बीच का निर्गत पंजी को चोरी कर गायब कर दिया गया है जिस बात की पुष्टि स्वयं सहायक निवेदक, खान, पटना ने अपने कार्यालय पत्र पत्रांक 150/एम. 2017 से होती है। निर्गत पंजी के अलावे उससे संबंधित संचिका को भी चोरी कर गायब कर दिया गया जिस कृत में करोड़े रुपये का राजस्व चोरी किया गया है। मामला विभाग मे सुनवाई हेतु लघित है। श्री यादव ने कहा की बालू का परिवहन चलान जो ट्रक की जगह स्कूटर से किया गया है जिसका खुलासा बिहार एजी ने पिछले दिनों किया है, जिसमें 355 करोड़ रुपये का कर चोरी किया गया है। उन्होंने कहा की मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रोहतास, गया का मामला अभी पीछे है, जो अगले एप्रिल मे वर्णन किया जाएगा।

मानीय मुख्यमंत्री के साथ भविष्य ख्याति युवा चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव से बिहार के लोगों को अभी ढेर सारी उम्मीदें बढ़ी हैं, देखना है आगे किस दिशा में बिहार को खींचते हैं फिलहाल ...। ●



● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

ज

ब राजा निरंकुश हो जाता है तो शासन पर उसका नियंत्रण हटकर अधिकारियों के हाथ में चला जाता है इसका दुष्परिणाम जनता को पहले राजा को बाद में भोगना पड़ता है। सत्ता की अस्थिरता, जातीय राजनीति ने शासन को केवल लोकतुंभावन कार्य तक ही सीमित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के बिहार के विभागीय मंत्री को स्वास्थ्य सहित 5 विभागों के मंत्री पद का जिम्मा है, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के चेहरा भी हैं। आज इस बात से इंकर नहीं किया जा सकता है कि 5 विभागों वाले मंत्री तेजस्वी यादव अपने विभाग पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई फाइल उनके हस्ताक्षर के बिना धूल फांक रहा है। उनका काम उद्घाटन समीक्षा या

कभी कभार औचक निरीक्षण तक ही रह गया है। विभागीय प्रमुख सचिव बिहार के दो बड़े विभागों के प्रमुख हैं, जिनके संयोग से मंत्री भी एक ही हैं। विभागीय प्रमुख ऐसे तो इस विभाग से उस विभाग में अधिकारियों तक को भी भेजते रहते हैं जिससे दूसरे विभाग का कार्य प्रभावित भी होता है।

स्वास्थ्य विभाग में ऐसे तो कई विशेष कार्याधिकारी हैं लेकिन विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु देवी का अपना एक अलग ही जलवा है, मुख्य सचिव के आदेश को भी ठेंगा दिखाती रहती है। न्यायालय तो इनके आगे नतमस्तक ही रहता है हाल में बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में अधिसूचना निकाली जिसमें 229 डॉक्टरों

को विभिन्न जगहों पर पदस्थापित किया गया, इसमें मुख्य सचिव बिहार के आदेश को ठेंगा दिखते हुए अधिसूचना विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया जबकि सरकार का सख्त आदेश है कि उप सचिव स्तर से कम के अधिकारियों को अधिसूचना निर्गत नहीं करना है। मुख्य सचिव तो छोड़िए जनाब मंत्री स्वास्थ्य के लिखित आदेश के बावजूद होस्पेटी के निदेशक श्याम सुंदर सिंह से कार्य लिया जा रहा है और सचिका श्याम सुंदर सिंह को मार्क किया जा रहा है जबकि वर्तमान मंत्री द्वारा पूर्व के मंत्री का आदेश

अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में लोकलुभावन की घोषणाएं तो रोज हो रही है, लेकिन भ्रष्ट और फर्जी अधिकारियों पर सरकार की एक नहीं चल रही है विभागीय अधिकारी प्रमुख के पास बिहार के दो प्रमुख विभाग हैं और विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री सहित पांच विभागों के मालिक हैं जिसके कारण विभागीय प्रमुख और उप मुख्यमंत्री महोदय का पकड़ विभाग से ढीला हो गया है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी अधिकारी उठा रहे हैं सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार खुद अपना नियम और संवैधानिक तरीकों से तोड़कर रेणु कुमारी को प्रोत्साहित कर उनसे अधिसूचना जारी करवा रही है। क्या विभागीय प्रमुख और उप मुख्यमंत्री महोदय के बीच की कड़ी मार्क कुमारी के हाथ कोई साक्ष्य लग गया है, जिसके कारण विभागीय नाव बिना नाविक के चल रहा है? आरिंदर इस राज पर से पर्दा कब उठेगा? केवल सच जल्द ही राज को आम जनता के बीच लाएगी, यह बाद रहा हमारा। ●



संवार बाजार
सारांश विभाग
विभागीय
प्रमुख

पटना, दिनांक- 30/12/2022

अधिसूचना नं-002-/टी०-०७/२०२१ -२०२३/राज. विभागीय विभागों से मीलावन का प्रमाणांकन का प्रमाणपत्र है। प्रधानमंत्री जनता से सम्पर्क-१ से २२९ तक से अधिक संस्थान/उद्योग विभागों परिवर्तितीय विभागों के विभागीय विभागों में, तस्मै-५ में अधिक पद पर अपने जारीसे हक्क विभागीय विभाग का प्रमाणपत्र दिया जाता है-

संख्या नं/प्रदान का नाम	विभागीय विभागों का नाम	मुख्य विभाग से संबंधित विभाग का नाम	विभाग से योग्यता
1 2	3 4	5 6	
1 5411/2008 DR. RENU SINGH	PATNA DISTRICT - PATNA	PLACE - D.C.I., AGARWAL	ADDITIONAL DIRECTOR
2 6274/2008 DR. AKHILESH KUMAR	PATNA DISTRICT - PATNA	PLACE - R.A.D OFFICE, PATNA	R.D.O. (IMMUNISATION)
3 6464/2008 DR. SUJYOTI KUMAR	PURNA DISTRICT - PURNA	PLACE - D.C.I. OFFICE, PURNA	R.D.O. (CO)
4 7029/2008 DR. DIPAK KUMAR PATEL	PURNA DISTRICT - KATHAR	PLACE - D.C.I., PHALKA	GENERAL MEDICAL OFFICER
5 8181/2008 DR. ARVIND KUMAR	MUNGIR DISTRICT - KHAGARIA	PLACE - S.H. KHAGARIA	GENERAL MEDICAL OFFICER
6 8433/2008 DR. DEEPMALA PRAKASH	BHAGALPUR DISTRICT - BHAGALPUR	PLACE - S.H., BHAGALPUR	GENERAL MEDICAL OFFICER
7 10247/2008 DR. VIJAY KUMAR CHAUDHARY	GAYA DISTRICT - PATNA	PLACE - PATNA MUNICIPAL CORPORATION	GENERAL MEDICAL OFFICER
8 10669/2008 DR. SHIKHA	MADHUSUDAN DISTRICT - PATNA	PLACE - P.M.C., PATNA	GENERAL MEDICAL OFFICER

25					
प्रबंधन	प्रबंधन	विभागीय	प्रबंधन	प्रबंधन	प्रबंधन
नं/प्रदान	नं/प्रदान	विभागीय का नाम	नं/प्रबंधन	प्रबंधन का नाम	प्रबंधन
1 229 HR0015044006378	DR. MUSAFAAN BHARTI	PATNA DISTRICT - JEHANABAD	GENERAL MEDICAL OFFICER/Posted at General place of General Surgeon in their own pay scale	GENERAL MEDICAL OFFICER/Posted at General place of General Surgeon in their own pay scale	

- उल्लंघनरहित सामाजन-विभागीय सिलसाल परिवर्तितीय को नियंत्रण दिया जाता है कि वे पदस्थापित तथा पर तुरत योग्यता देना योग्यता करे।
- संबंधित अधिक राज्य विभाग-एवं-मुख्य विभागों परिवर्तितीय को नियंत्रण दिया जाता है कि उनसे सिलसालों के पदस्थापन अतिरिक्त हो जाने की स्थिति में विलापाता दिया रखाया गया है कि सिलसालों के पदस्थापन में सामाजिकिता करते हुए दिया जाए।
- उक्त पदस्थापित सिलसालों में से ऐसे सिलसाल विभागीय व्यापक स्तरीय हो जाना है कि वे प्रदान दिया जा सकता है कि उक्त पदस्थापन में सामाजिकिता करते हुए दिया जाए।

विहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)
विभागीय
प्रमुख

जागतिक २-टी०-०७/२०२१-२०२३(२). पटना, दिनांक 30/12/2022.

प्रतिलिपि-आधिक सचिवालय मुख्यमंत्री, पटना विभाग, विहार राज्यपाल के आदेशान्वयन में प्रकाशनामात्र प्रतिलिपि।

प्रतिलिपि-हाइकोर्ट, विहार, बीरबल पटेल एवं पटना विभागों प्रतिलिपि।

प्रतिलिपि-संसदीय अधीकारी एवं संसदीय विभागीय विभागों प्रतिलिपि।

प्रतिलिपि-संसदीय अधीकारी एवं संसदीय विभागीय विभागों प्रतिलिपि।

जिला उद्योग केन्द्र जमुई के महाप्रबंधक नरेश दास भ्रष्टाचार में लिपा

• शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

वि

हार का उद्योग विभाग डपोरशंखी घोषणाओं के लिए जाना जाता है। यह सरकार के लिए सफेद हाथी बन कर रह गया था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से नई ऊर्जा के साथ बिहार को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का बिहारी उद्योगपति को बिहार में उद्योग लगाने का नारा देकर बिहार में जो औद्योगिक विकास का आयाम खड़ा किया जा रहा है वह काबिल तारीफ है। बिहार सरकार का उद्योग स्टार्टअप नीति भी तारीफ के काबिल है। बिहार सरकार अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाते हुए आगे बढ़े तो जो उद्योग विभाग बिहार के विकास के लिए मील का पथर साबित होगा।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौडिक के विभाग में उनके महाप्रबंधक ही भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनिमियता करवाने में माहिर खिलाड़ी निकले। जिला उद्योग केन्द्र जमुई के महाप्रबंधक नरेश दास जो अपने पदस्थापना काल 20 जुलाई 2020 से महाप्रबंधक के पद पर



नरेश दास

रहते विभागीय आदेश के विपरीत कार्य करते पकड़े गए। पटना से आरटीआई एक्टिविस्ट श्री त्रिभुवन प्रसाद यादव के शिकायत पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग ने रातों-रात महामहिम राजयापाल से अनुमति लेकर 17 दिसंबर को निलंबित कर दिया। तत्कालीन महाप्रबंधक को निलंबन की सूचना दिये जाने के पश्चात चार दिनों तक देर रात्रि जिला उद्योग केन्द्र जमुई में

कार्य करते देखा गया, जिसकी भी शिकायत उद्योग विभाग बिहार पटना के अधिकारी को दिया गया। मामले में श्री त्रिभुवन प्रसाद यादव ने कहा की श्री नरेश दास अपने प्रथम पोस्टिंग जिला उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। उस वक्त भी इन्हें विभागीय कार्य में लापरवाही एवं वित्तीय अनिमियता के कारण निलंबित किया गया था, इसके बावजूद इन्हें जिला के महाप्रबंधक के पद पर बैठा कर कार्य करने का अवसर दिया गया, बावजूद ये अपने आचरण से बाज नहीं आये। महाप्रबंधक की करतूतों को लेकर नवंबर 2022 के आखिरी महीने में एक शिकायत पत्र विभाग को दिया गया। इसके पश्चात् साक्ष्य के साथ निगरानी विभाग बिहार सरकार से साक्ष्य प्रस्तुत कर वित्तीय अनिमियता एवं विभागीय गाईड लाइन के विपरीत किये कार्य की जाँच कर कार्रवाई

15:08

10:40 AM 74%



नरेश कुमार's post



नरेश कुमार is at Jamui district.

...

ये है तितिवाद राजनीति, बैकर्ड और फारवर्ड, महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, जमुई नरेश दास जो को साजिश की तहत फंसाया गया है, उन्होंने असीम में पदव्युत पित वित्तीय अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिपा था उसे सर्वोत्तम किया था और बात में विसं अधिकारी को सर्वोत्तम किए थे उन्हीं का कोई दिशदादा ही विभाग के शीर्ष स्तर पर (DIRECTOR) डायरेक्टर के पद पर विदायित निकला जो कि उन अधिकारी को भ्रष्टाचार के घासे में डाल पर विदायित निकला जो कि उन डायरेक्टर ने नरेश दास (GM, Jamui) के जाति चामर पर भी भ्रष्टाचार के उच्च स्तरीय साक्षी भी दीया गया है, #जाति के जाती चामर ही उच्च स्तरीय जाती होनी चाहिए।

उद्योगीयों से पैसे लेने के मामले में उद्योग पदाधिकारी सरपें



8

8



Most relevant ▾



Like Reply

"Most relevant" is selected, so some comments may have been filtered out.



सेवा में, उद्योग समीक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पदार्थ : TP/27/12 फैला - 05/11/22
विषय - जिला उद्योग केन्द्र जमुई के महाप्रबंधक श्री नरेश दास द्वारा किये गये विरोध अनिमियता के संबंध में। महाराज,	
उपरोक्त विषयक सुचित करना है कि,	
<p>जिला उद्योग केन्द्र जमुई के महाप्रबंधक श्री नरेश दास भ्रष्टाचार में लिपा है जो स्थानीय दासों के सहायता कर सकते योजनाओं में भी रास्ता लेकर सकारी तरफ विवादीय नियम के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं जिससे सरकार एवं संघर्षतंत्र समीप अनिमियता एवं भ्रष्टाचार कर जाने कार्रवाई की जगह आवाज है जो निमलिखित विकास के उत्तरांश करने के लिये दीर्घीय घाविकारियों से जाँच करने के उत्तरांश स्थानीय जायेगी।</p> <p>1. श्री वराहन कुमार (हासिरहड़), श्री दीपेंद्र कुमार (ग्राम-संसाधन) आदीय संसाधन - CMEDC 20217667412128 एवं श्री गोपन कैशीरी (पुरुषी वाजाह) जमुई के हवाने वाले हैं जो जिला कुमार इनके जिजीके लिये जाइएगार हैं।</p> <p>2. संदीप कुमार (ग्रा - संसाधन) को DRPM उधमीयों को जाने वाले हैं जो प्रमाणित दास के सफल कियायन्हैं तैयार करने के लिए उन्होंने जिला का लेन-देन करते हैं। ऐसे खाली से एक उमस को DRP बनाने के पीछे एक मात्र उद्देश्य यही होगा कि अपने पास, सरकारी कार्यालय में बैठा कर ऐसी को अवैध लेनदेन करने में आसानी ही संभव।</p> <p>3. दीपी कार्यालय का एक दूसरा DRP श्री गोपन कैशीरी (चार्टर्ड अकाउंटेंट CA) पुरानी बाजार का रहने वाला है जो बहिमान में उप स्थानीय कंट कार्यालय है जिससे भी महाप्रबंधक द्वारा 50,000/- रुपये द्वारा लेकर DRP बन दिया गया ताकि सरकारी दफ्तर में बैठक श्री दास के लिये अवैध वसूली में सहयोग करते हों।</p>	
<p>1. Name of Vehicle's Owner : MANJU DEVI 2. Father's guardian's Name : RAJENDRA KUMAR KUWAD, DEDHUA 3. Address : KALABANJ, CHITRAYA, Post Office : DEOLAHAR Village : CHITRAYA, Distric : JAMUI, Pincode : 853252 Police Station : SEKHRI, District : JAMUI State : JHARKHAND, Pin No : 81411123</p> <p>4. Mobile Number : 9704543545 5. Aadhar Number : 645182778566 6. PAN Number : AEOPDPA47K HBS 5003646 7. EPIC Number : 8. Email Address : (Note: Enclose Copies of proof of identity & Proof of Address)</p> <p>9. Bank Details : Name of Bank : SBI Name of Branch : KUNDA (DISTT. DEOLAHAR) Bank Account No. : 5812327754 IFSC Code : SBIN007150</p> <p>10. Vehicle Details : Name of Vehicle : STORMPIO RF HAWK BS3 Type of Vehicle Private/Commercial : PRIVATE Vehicle Registration No. : JH 157 4547 Vehicle Owner Book No. : 0679460 Rent/Month (in Rupee) : 3000/- PER MONTH 11. Name of Office : DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, JAMUI Declaration : I hereby declare that the details given above are true and correct to the best of my knowledge and belief. Place : JAMUI Date : 28/10/2023 Attestation by Officer : M.J.D. Date : 28/10/2023 Signature of Vehicle's Owner : नरेश दास</p>	

करने का आग्रह किया गया, जो उपरोक्त तिथि 17 दिसम्बर को निर्वाचित कर मुख्यालय पटना में 24 घंटे के भीतर योगदान देने का निरेश दिया गया। किन्तु श्री दास ने ऐसा नहीं कर चार दिनों तक जिला उद्योग केंद्र जमुई में डाटा ऑपरेटर एवं प्रधान लिपिक से मिलकर साक्ष्य मिटाने एवं दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते रहे, जिनके विरुद्ध मैंने पूर्व में सूचना की मांग किया था। प्रारंभकाल से सरकारी सेवा में पद पर रहते हुये इनके द्वारा बिम इवावा पर नाम बदलकर जातीय गोलबंदी किये जाने, ब्राह्मणवाद पर लेक्चर देने, धार्मिक देवी-देवताओं पर टीका-टिप्पणी किये जाने, केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखने सहित चुनाव में ईवीएम मशीन की धांधली सम्बंधित बयान लिखकर सार्वजनिक रूप से एफबी इंटरनेट पर डाला जाता रहा था। ताजुब की बात है की वर्षों से ऐसा करते रहने के बाबजूद चुनाव डृढ़ी में इहें लगाया गया। ईवीएम के संबंध में इहें जानकारी के अलावे वोट किसी का पड़े हो, सरकार किसकी बनेगी इन्हें मालूम रहती थी। इसके बाबजूद बिहार की सरकार ने इहें चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नहीं बनाया, जिसकी लिखित शिकायत महामहिम राज्यपाल, बिहार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सहित संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। श्री नरेंद्र जी का नरेन्द्र कुमार के दो नामों से एफबी पर अकाउंट बना कर वर्षों से संचालित किया जा रहा था, जिसमें इनके सभी साक्ष्यों के साथ,



संदीप पौंड्रिक

STATEMENT OF ACCOUNT					
APR Automobiles Pvt. Ltd. (Authorized Dealer for Mahindra & Mahindra Ltd.) Vrindavan Glass House, Sector 1, Dehradoon Muzaffarnagar - 247001 U.P. India GSTIN: 18AAECA497ZEZA TEL: 0515-25550492 QUOTATION FOR MAHINDRA VEHICLE Date: 21-06-2022 Ramesh Tourism Taxi Muzaffarnagar U.P. INDIA 21-06-2022 Statement From: 01/06/2022 To: 21/06/2022 Date: 21/06/2022 Time: 13:06:34 Name: JAMES BRANCH Address: 1ST FLOOR, KAMALA ROAD Dehradoon U.P. INDIA Branch Code: 2105 Phone No: 0515-25550492 Account No.: 7036563122 Product : CNG-GEN-PUB Currency : INR Page No.: 1 Inv. Rate: 12.95% p.a. Post Dt Val Dt Details Cr. Amt Debit Credit Balance Brought Forward Normal Balance Unclaimed Amount Drawing Power Due Date Due Date Total Normal Insurance Zero Depth Registration RSA Shield Total Terms & Condition Price payable on the day of delivery shall be charged, irrespective of when advance payment or order is received. Demand Draft/Bill Of Lading amount to be made in favor of APR Automobiles Pvt. Ltd. payable at Gaya. All amounts shall be subject to change without any prior notice. No interest will be paid on any advance payment. Force majeure will not apply if there is any delay in delivery of vehicle due to circumstances beyond your control, delivery period shall be extended. Any dispute arising out of this transaction will be subject to jurisdiction of GAYA COURT ONLY. Bank's Name Ac No. IFSC Code H.D.F.C. Gaya 0421250002511 HDFC000421 Signature of Purchaser / Purchaser's Representative (Authorised Signatory)					

एफबी पर किये गए पोस्ट के प्रिंट आउट निकाल कर संबंधित अधिकारी को कार्रवाई हेतु अलग से दिया गया है।

जिला उद्योग केंद्र जमुई में महाप्रबंधक के पद पर काबिज रहे श्री नरेश दास ने विभागीय नियम के विरुद्ध मोटी रकम लेकर कई डीपीआरओ बनवाये जिसमें प्रमुख नाम जयराम कुमार, संदीप कुमार, गौतम केशरी शामिल हैं जो एक को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी बनाया गया है। एक जो एक्सिस बैंक में नौकरी करते हैं और एक स्वास्थ्य केंद्र में नियोजित कर्मचारी है जिसे डीपीआरओ बनाया गया है, जबकि विभागीय नियम के अनुसार दस हजार से अधिक आमदनी वाले को उद्यमी योजना सहित डीपीआरओ नहीं बनाया जा सकता। डीपीआरओ को प्रति लाभार्थी विभाग के तरफ से अनुदान के रूप में बीस हजार रुपये दिया जाता है। ऐसे परिस्थिति में इहें उद्यमी योजना के तहत इन सभी को दस लाख रुपये के लोन दिया गया, जो नियम के विरुद्ध किया गया कार्य है।

महाप्रबंधक द्वारा जिसे गाड़ी का किराये पर रखकर कार्यालय कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा था। वह झारखण्ड का निर्बंधित स्कार्पियो है। आश्चर्य की बात है की जिला उद्योग केंद्र जमुई में प्रधान लिपिक सह लेखा के कार्य देख रहे श्री निरंजन कुमार की धर्मपत्नी श्रीमति मंजू देवी के नाम से निर्बंधित है, जो प्रति माह तीस हजार रुपये के किराये पर झारखण्ड की गाड़ी रखी गई है, जबकि विभागीय नियम इसके विपरीत है इस संबंध में विभागीय निदेश

सभी जिले के महाप्रबंधक को भी दिया गया है। Jh15J 4547 Scorpio RF H W K BS 3, जिसका व्हीकल बुक नम्बर 00774960 है जो देवघर झारखण्ड के रहने वाले मंजू देवी के नाम से है जिनका पति उद्योग विभाग में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत श्री दास के लिए कार्य करते हैं जिनका मकान देवघर में 17 कट्टा जमीन पर निर्मित आलीशान मकान है जिसके अंदर बीस- बीस फिट के कमरा बना हुआ है।

उद्यमी योजना अंतर्गत रेमेश दास के नाम पर दस लाख रुपये देकर मुख्यमंत्री योजना का लाभार्थी बनाया गया। प्रथम किस्त की इक्वायरी करने के पश्चात दूसरा एवं अंतिम किस्त जारी कर दिया किन्तु यह रुपये गाड़ी के एजेंसी वालों को नहीं देकर जूते-चप्पल वाले दुकान को दे कर वित्तीय अनिमियतता की गई वही कॉमर्शियल गाड़ी की जगह प्राइवेट गाड़ी को लेने के बाबजूद लोन सेन्सन कर दिया जिससे श्री दास ने मोटी रकम लेकर ऐसा कृत किया जिसका भी साक्ष्य प्रस्तुत कर विभाग को कार्रवाई के लिए दिया गया है। श्री यादव ने कहा की जिले में वैसे दर्जनों लाभुकों को सभी किस्त जारी कर दिया गया जिसने कार्यस्थल पर कुछ भी उपकरण नहीं लगाया है नहीं गाड़ी की खरीदगी किया है जिस कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है। मामले में विभागीय सुनवाई 13 जनवरी को सुनवाई पर रखा गया। उन्होंने बताया की युवा उद्यमी के तहत लाभुक बनाने में भी अनिमियतता किया गया है जिसे खास लोगों के उधमी योजना के तहत लाभुक बनाया गया है जो सभी किस्त लेकर भी कोई कार्य नहीं किया है। ●



राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त निकले शिखंडी

नगर निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग शिखंडी की भूमिका में

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

वि

हर में ग्राम और नगर सरकार बनाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, जिसका मुख्यालय सोन भवन में स्थित है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया आयुक्त दीपक प्रसाद हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे तो स्वतंत्र इकाई है, लेकिन यह राज्य सरकार के एक विभाग के रूप में कार्य कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया दीपक प्रसाद ने इसे शिखंडी बना दिया है, साथ ही पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आयुक्त दीपक प्रसाद की भूमिका भी शिखंडी वाली ही रही है। पटना उच्च न्यायालय ने भी अपने 04/10/2022 के आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को समीक्षा करना चाहिए कि वह एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है वह विहार सरकार से बंधा हुआ नहीं है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया



124

18 comments 2 shares 1k views

Like

Comment

Share

Maheshwar Hazari

24 Sep 2022 ·

समस्तीपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद की उमीदवार श्रीमती संध्या हुंजारी जी के समर्पण समारोह का आयोग चुनाव के नामांकन सभा में विचार विमर्श करते हुए।



था कि यह चुनाव निर्दलीय होगा, लेकिन इस की धंजियां कमोवेश सभी पार्टियों ने मिलकर उड़ाया है। हद तो तब हो गई जब संवैधानिक पद पर बैठे विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हुंजारी ने खुलेआम इसकी धंजियां उड़ाते हुए अपनी पत्नी और समस्तीपुर से मुख्य पार्षद के प्रत्याशी श्रीपती संध्या हुंजारी को महागठबंधन की प्रत्याशी घोषित करते हुए जनसभा को भी संबोधित किया था। वहाँ दूसरी तरफ दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने दरभंगा में महापौर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा और उनके पति नवीन सिन्हा जो वार्ड नंबर 21 के पार्षद के प्रत्याशी थे, उनके पक्ष में खुलेआम कार्य करते देखा गया है।

दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने महापौर प्रत्याशी अंजली देवी और उनके पूर्व विधान पार्षद पति अर्जुन सहनी जब चुनाव स्थगित था, तब इसीलिए प्राथमिकी दर्ज करवा दिए कि छठ महापर्व की शुभकामना का बैनर लगाए हुए थे। उस बैनर में महापौर प्रत्याशी द्वारा कहाँ भी वोट देने की मांग नहीं की गई थी, वहाँ दूसरी तरफ महापौर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा को बिना

दरभंगा के जिलाधिकारी ने तो कमात ही कर दिया उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि हजारों की संख्या में मुर्दे ने वोट डाल दिया वार्ड नंबर-21 के बोटर का नाम शाहिद खातून, एपिक नंबर-FB1188242 और प्रतिमा कुमारी जिसका नंबर-BR/15/089/435235 ने अपने बोट का इस्तेमाल बूथ पर जाकर किया, जबकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, वहाँ दूसरी तरफ जो राज्य के बाहर रहते हैं, जैसे मोहम्मद उजाले और किरण कुमारी उनका भी बोटिंग हो जाता है। यही नहीं मतगणना में भी वह खड़े होकर वार्ड नंबर 21 के प्रत्याशी नवीन सिन्हा को 90 बोट से जितवा देते हैं और विरोध करने वाले निकटतम प्रत्याशी महादलित और अरुणेश चंद्र को भगा देते हैं, बेचारा महादलित अरुणेश चंद्र इसकी लिखित शिकायत उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग में करता करता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आयुक्त महोदय तो ठहरे शिखंडी, कोई कार्यवाही तो होनी नहीं थी सो हुई भी नहीं। यही नहीं नवीन सिन्हा के कई बोटों का नाम दूसरे वार्ड से आकर वार्ड नंबर 21 में जुड़ जाता है। इससे भी बड़ी बात कि कई बोटर का नाम कई कई बार्डों में होता है पर आपत्ति के बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग और दरभंगा के जिलाधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। यह सब तो एक उदाहरण मात्र है कई ऐसी अनियमितता है जो यह नगर निकाय चुनाव चुनाव ना होकर एक सोनी समझी साजिश होकर रह गई है।

पटना के जिलाधिकारी महोदय ऐसे तो व्यस्त ज्यादा रहते हैं लेकिन पटना में भी बड़े पैमाने पर बोटों की हेराफेरी हुई है। वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रत्याशी विशाल कुमार सिंह के अपने पिता अशोक सिंह, भाभी विनीता, शालिनी, चाचा बृजकिशोर सिंह, भाई आनंद मोहन, बहन टीना सहित हजारों नाम साजिश के तहत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर जाता है, जिसकी शिकायत विशाल कुमार सिंह ने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग से की। लेकिन आयुक्त महोदय तो ठहरे शिखंडी कोई कार्यवाही नहीं हुई पटना के नगर निगम क्षेत्र में फर्जी तरीके से ग्रामीण इलाकों से लाकर बोटर को जोड़ा गया और यही बोट निर्णयक सिद्ध हुआ है।

वहाँ दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में भी राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका कमोवेश शिखंडी वाली ही रही है। आपत्ति के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, लेकिन चुनाव आयोग मौन धारण किए हुए था। ऐसा ही एक

सेवा में,
आयुक्त महोदय
राज्य निर्वाचन आयोग
सोन भवन पटना, बिहार

विषय — दरभंगा वार्ड 21 के नगर निगम की चुनाव के मतगणना में धांधली के संबंध में।

महाशय, मैं नगर निगम वार्ड 21 के चुनाव का प्रत्याशी हूं। दरभंगा वार्ड 21 नगर निगम के चुनाव के मतगणना के परिणाम में धांधली हुई है। वार्ड 21 के हर बूथ के ईवीएम में दिखाए जाने वाले परिणाम में कुछ डिजिटल ऐरर आ रहा था। जिससे संख्या सही दिख नहीं रहा था। जिसके लिए मैंने पूर्णिवरोध कर दुबारा मतगणना करवाने की मांग किया। मेरे इस विरोध से नगर निगम वार्ड 21 के चुनाव का परिणाम सुनाने में बहुत देर तो हुई, लेकिन दुबारा मतगणना नहीं किया गया। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं की। इस मतगणना के ईवीएम मशीन के इस गड़बड़ी से मतगणना सही से नहीं हो पाया। अतः मैं महाशय से निवेदन करूँगा 21 वार्ड सभी ईवीएम मशीन सही से रखकर दुबारा से मतगणना कर सही परिणाम सुनाए।

Arunesh Choudhary

आपका विश्वासी

अरुणेश चंद्र

9220535488

प्रतिलिपि - माननीय मुख्य सचिव महोदय, बिहार, पटना

वाक्या समस्तीपुर जिले के वारी पंचायत का है, जिसके मुखिया जगन्नाथ पोद्दार हैं जो कि वैश्य बनिया जाति से हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट वारी पंचायत से चुनाव लड़ा और जीता था। उनके निकटतम प्रत्याशी रामकृष्ण पंडित ने चुनावों में इस संबंध में परिवाद डाला, जिसका चुनाव

केस नंबर-32/22 है। अब यह मामला आयुक्त दीपक प्रसाद से नहीं संभला तो आयुक्त महोदय ने यह मामला सामान्य प्रशासन विभाग के जाति निर्धारण समिति को भेज दिया। आज साल भर बीत जाने के बावजूद फाइलें धूल फांक रही हैं और मुखिया जगन्नाथ पोद्दार आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के आशीर्वाद से मौज ले रहा है।●

2024 और 2025 चुनाव में भाजपा संगठन का कौन कहेगा नेतृत्व?

केन्द्रीय नेतृत्व से फिर से संजय जायसवाल का नाम लगभग फ़ाइनल



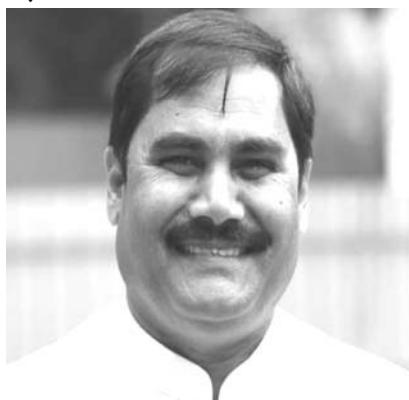
संजय जायसवाल

● सागर कुमार

19 80 में आम चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया और केवल 31 सीटों पर जीत हासिल की। अप्रैल 1980 में, चुनावों के तुरंत बाद, जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् ने अपने सदस्यों को पार्टी और आरएसएस के 'दोहरी सदस्य' होने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके जवाब में, जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए छोड़ दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। और जब पार्टी के राष्ट्रीय कमान देने की बात आई तब अटल बिहारी वाजपेई को भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हमारा यह आर्टिकल बिहार के परिप्रेक्ष्य में है इसलिए हम बिहार भाजपा के शुरुआती दिनों में ले चलते हैं।

1980 में पार्टी की स्थापना के समय कैलाशपति मिश्र पहले भाजपा बिहार अध्यक्ष बने। उन्होंने 1995 से 2003 तक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उक्त भूमिका के बाद अब वर्तमान अब पुनः हम आते हैं अपने आर्टिकल पर, कि तमाम अटकलों और तमाम चर्चाओं के बाद भी आखिर किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी बिहार अपना लीडर यानी कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, बड़े-बड़े पॉलिटिकल पटिंगों के लिए भी चुनावी बना हुआ है कि आखिर भाजपा

बिहार का अगला प्रदेश अध्यक्ष फिर से संजय जायसवाल होंगे या फिर कोई और नया चेहरा। और अगर कोई नया चेहरा होगा तो वह कौन होगा यह बड़ा प्रश्न केवल बिहार ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी नेताओं के बीच में अत्यंत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इस बार के जो भाजपा बिहार के अध्यक्ष होंगे उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी जवाबदेही रहेगी। एक तो भाजपा इस बार अकेले चुनावी मैदान में है और 2024 में लोकसभा का चुनाव और ठीक उसके 1 साल बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी आने वाले प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही होना तय है। जहां जदयू और राजद ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को रिपीट किया है वहीं कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। अब भाजपा जाति समीकरण को भी साधना चाहती है और एक ऐसे अध्यक्ष के तलाश में है जिसकी संगठन पर मजबूत पकड़ हो, विश्वासी हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो, इस बजह से इस बार के अध्यक्ष के चयन में भाजपा फॉक-फॉक कर कदम रखना चाहती है और केन्द्रीय नेतृत्व के कई बैठकों में, कई नामों के चर्चा होने के बाद भी अभी तक भाजपा बिहार नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी तय होना अभी बाकी है और उसके बाद ही बिहार की तरफ भाजपा के कदम बढ़ेंगे।



जनक चमार



तारकेश्वर प्रसाद

वर्तमान अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल 14 सितंबर 2022 को ही खत्म हो गया और अभी वह एक्सटेंशन पर हैं। क्या संजय जायसवाल फिर से होंगे रिपीट? भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक बिहार के बेतिया क्षेत्र से लगातार तीन बार लोकसभा के सदस्य रहे स्वर्गीय डॉक्टर मदन प्रसाद जयसवाल के पुत्र, डॉ संजय जायसवाल, जो कि खुद 2009 से लगातार तीसरी बार पश्चिम चंपारण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक सफल कार्यकाल उन्होंने दिया है। जयसवाल जी पेशे से डॉक्टर हैं, इनके पिता भी बिहार के जाने-माने डॉक्टर थे और उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। आपको याद होगा संजय जायसवाल ही वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने सर्वप्रथम नीतीश कुमार, शराबबंदी और बिहार में अधिकारियों के दादागिरी पर सवाल उठाया था और लगातार उठाया था। गठबंधन में रहते हुए भी संजय जयसवाल लगातार आक्रमक रहे और नीतीश कुमार को सीधी टारगेट करते रहे। इसके बाद बिहार में हुए उपचुनाव में भी संजय जयसवाल की दमदार भूमिका मानी जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुटुंबी का चुनाव भाजपा संगठन के साथ-साथ संजय जयसवाल के ही मेहनत का नतीजा है क्योंकि संजय जयसवाल ने खुद बूथ स्टर की कैपेनिंग करके गांव-गांव घूमकर नीतीश कुमार के बोर्टों को भी टर्नअप कराया। इसके साथ-साथ डॉक्टर संजय जयसवाल कई सामाजिक कार्य भी करते हैं। भाजपा संगठन

भाजपा युवा मोर्चा का नेतृत्वकर्ता कौन?



दुर्गेश तिवारी



मनीष सिंह



धर्मेन्द्र तिवारी

क्या युवा मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गेश सिंह की नहीं होगी वापसी? :- डुमरांव के युवा नेता दुर्गेश कुमार सिंह के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल तो लगभग ठीक ही रहा। परंतु पार्टी के अंदर खाने में खासकर युवा मोर्चा में यह खबर चर्चा में है कि दुर्गेश सिंह की छवि प्रदेश नेतृत्व के लोगों तक ठीक नहीं बन पा रही है। चाहे औरंगाबाद विवाद हो या फिर कार्यकर्ताओं में सामंजस्य स्थापित करने की बातें। इन तमाम वजहों से शायद इस बार दुर्गेश सिंह प्रदेश नेतृत्व को नहीं भा रहे हैं। खैर शुरुआती दिनों में उन्होंने बिहार का ताबड़तोड़ दौरा किया, टीम को मजबूत किया और चुनाव में भी अच्छी भूमिका निभाई परंतु फिर भी उनकी छवि साफ-सुथरे और सुलझे नेता के रूप में बिहार प्रदेश में नहीं बन पाई और यही कारण है कि बहुत सारे कार्यकर्ता दुर्गेश सिंह से जहां नाराज चल रहे हैं वहीं बहुत सारे प्रतिद्वंदी भी दुर्गेश सिंह को उनके कुर्सी से हटाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।

धर्मेन्द्र तिवारी हो सकते हैं भाजप्युमो बिहार के अगले प्रदेश अध्यक्ष :- अखबल जिले के काफी सामान्य एवं पुराने भाजपाई परिवार से आने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तृतीय वर्ष प्रशिक्षित युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री धर्मेन्द्र तिवारी की अगले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे मजबूत दावेदारी बन रही है।

मनीष सिंह की भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मजबूत दावेदारी :- मनीष सिंह की भी छवि साफ-सुथरी और सांगठनिक कार्य कुशल व्यक्ति के रूप में है। पटना महानगर अध्यक्ष रहते हुए मनीष सिंह ने कई ऐसे कार्य किए जिस से प्रभावित होकर प्रदेश नेतृत्व ने इनका नाम युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए भेजा और वर्तमान में गुजरात के प्रभारी भी हैं। राजपूत समाज में इनकी गहरी पैठ है और पटना में हर समय आप इन्हें किसी ने किसी सामाजिक कार्य में सम्मिलित हुए देख सकते हैं इसके अलावा यह सांगठनिक कार्यों से पूरे देश का भ्रमण करते हैं। सांगठन में

मजबूत पकड़ है। प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर के नेताओं तक भी इनकी सीधे पहुंच मानी जाती है और कहा तो यह भी जाता है कि मनीष सिंह पटना के वर्तमान सांसद पूर्व कानून मंत्री रवीशंकर प्रसाद के करीबी लोगों में से है इसी बजह से इनका भी नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत जोरों से चल रहा है।

अनमोल शोभित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ा विकल्प :- बेतिया जिला के संग्रामपुर बरियरीया के रहने वाले भाजपा आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के सहसंयोजक, भाजप्युमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सह लद्दाख प्रभारी और इंडोनेशिया में होने वाले जी-20 कार्यक्रम में वाई-20 आयोजन समिति के अध्यक्ष अनमोल शोभित वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल के सबसे अधिक करीबी माने जाते हैं। स्वभाव से काफी सरल और सहज रहते हैं। संगठन के कार्यों में अत्यंत रुचि और सांगठनिक कार्यकुशलता में महारात हासिल है। समस्त बीजेपी महकमे में यह चर्चा जोरों पर है कि अगर संजय जायसवाल दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो युवा मोर्चा की कमान अनमोल शोभित को ही दी जाएगी। परंतु फिर यहां पर अगर जाति का दांव चला तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक जाने में समस्या हो सकती है।

युवा मोर्चा के अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कई लोगों का चल रहा है नाम :- राजपूत समाज से मनीष सिंह के बाद अगर किसी नेता का अध्यक्ष के तौर पर नाम आता है तो वह है राज राजेंद्र सिंह। राज राजेंद्र सिंह पेशे से व्यवसाई हैं। उनकी पृष्ठभूमि संघ से बताई जाती है। वर्तमान में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है और यह राधा मोहन सिंह के करीबी बताए जाते हैं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले सीतामढ़ी के बथनाहा सीट से युवा विधायक, पूर्व में रिलायंस में इंजीनियर रहे अनिल कुमार (राम) की भी प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी बहुत तगड़ी मानी जा रही है।

आशीष सिंहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कदावर



अनमोल शोभित



आशीष सिन्हा



विक्की राय

नेताओं में से एक :- 2012 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 28 साल बाद हुए चुनाव में अध्यक्ष पद जीत कर बिहार में चर्चा में आने वाले पटना के कुम्हरर विधानसभा के विधायक अरुण कुमार सिन्हा के पुत्र आशीष सिन्हा भी भाजपुमो के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी दावेदारी तेज कर दी है। आशीष सिन्हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कदावर नेताओं में से एक रहे हैं और वर्तमान में भाजपुमो के प्रदेश मंत्री के रूप में भी इनका कार्यकाल शानदार रहा है। इनकी विशेषता यह है कि इन्हें जो भी प्रभार दिया जाता है उसको काफी कार्य कुशलता पूर्वक करते हैं और चुनाव जिताने में इन्हें महारात हासिल है। हाल ही में पटना में हुवे मेयर और उप मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार की प्रचंड विजय हुई है तो उसमें अहम भूमिका आशीष सिन्हा की मानी जा रही है। इसके साथ साथ संगठन के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं में भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। विधायक पुत्र होने के नाते और संगठन में काफी दिनों से कार्य करने के कारण प्रदेश के और केंद्र के लगभग नेताओं से सीधे संपर्क में हैं। मीडिया फ्रैंडली है और सबसे बड़ी बात है नेतागिरी करने भी जानते हैं। इस बजह से इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के चर्चाएं जोरों पर है खासकर विद्यार्थी परिषद से अगर किसी का नाम आगे जाता है तो उसमें आशीष सिन्हा और विक्की राय प्रथम दृष्टया होंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कदावर छात्र नेता विक्की राय :- भूमिहार समाज से आने वाले युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कदावर छात्र नेता भाजपुमो के वर्तमान प्रदेश मंत्री विक्की राय भी प्रदेश अध्यक्ष कि रेस में हैं। माना यही जा रहा है कि अगर भूमिहार जाति से भाजपुमो प्रदेश अध्यक्ष बनाया

में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं।

कार्यकर्ताओं से सीधी वार्ता करते हैं, कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पहचानते हैं सीधे और सरल व्यक्तित्व वाले हैं। और सबसे

बड़ी बात कि भाजपा में आमतौर पर हर एक नेता का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी है परंतु संजय जायसवाल एकमात्र ऐसे नेता है जो सर्वमान्य है और भाजपा संगठन बिहार को वर्तमान परिपेक्ष में करीब से देखा जाए तो बिहार में संजय जायसवाल

जाता है तो उनमें सबसे पहला नाम विक्की राय का ही आता है। हालांकि औरंगाबाद और पटना में हुए घटनाओं के बाद विक्की राय के प्रतिद्वंदीयों की संख्या काफी हो गई है। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही आए हुए बिहार के पुराने और कदावर छात्र नेता हिमांशु यादव का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उभर कर आता है क्योंकि नित्यानंद राय के करीबी छात्र नेताओं में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वह हिमांशु यादव है। हालांकि हिमांशु यादव कुछ दिनों से संगठन में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं परंतु हिमांशु यादव पुराने और काफी तीव्र बुद्धि वाले छात्र नेता माने जाते हैं। अपने ओजस्वी भाषणों से अपनी छाप छोड़ने वाले और पटना के युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय हिमांशु यादव, यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश नेतृत्व की पहली पसंद बन सकते हैं। विक्की राय के बाद भूमिहार समाज से अगर किसी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आता है तो वह है सारण जिले के आयुष राय का। आयुष राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरी पिछी के कार्यकर्ता हैं। इनका परिवार पुराना संघी रहा है। काफी संभ्रांत परिवार से हैं और वर्तमान में भाजपुमो में प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। भूमिहार समाज से यह भी प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है की अध्यक्ष के रूप में नितिन अभिषेक और जितेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल रहा है।

अंत में फिर से हम बताना चाहेंगे कि उपरोक्त सभी नामों की केवल चर्चा मात्र है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का बंटवारा और क्रिकेट का स्कोर बोर्ड कब कैसे बदल जाए आखरी दांव तक कोई भांप नहीं पाता।

और नित्यानंद राय से बड़ा चेहरा और कद फिलहाल नहीं दिखता है। केवल सच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से बिहार भाजपा और केंद्रीय टीम के कई बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं से आगामी प्रदेश अध्यक्ष के विषय में चर्चा की



अजय निषाद



प्रदीप सिंह



संजीव चौरसिया

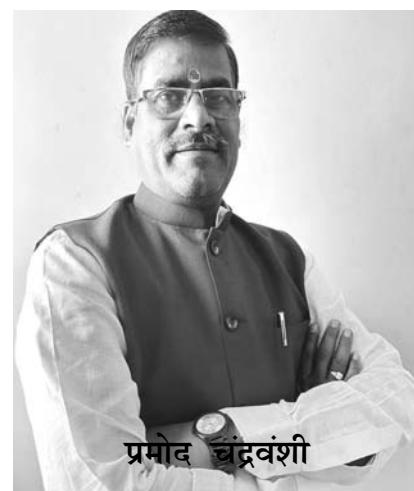
और उसी आधार केवल सच का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल जी पुनः रिपोर्ट होंगे इसकी संभावना 90% से अधिक है।

☞ संजय जायसवाल का एक स्थाह पक्ष यह भी :- 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी लड़ाई थी। लालू यादव के जगल राज के खिलाफ भाजपा नीतीश कुमार के साथ मिल कर लड़ रही थी। मदन जायसवाल, जो कि संजय जायसवाल के पिता थे, वे चाहते थे कि बेतिया विधानसभा क्षेत्र से बेटे संजय जायसवाल को भाजपा टिकट दे, लेकिन भाजपा ने संजय जायसवाल को टिकट नहीं दिया। भाजपा ने टिकट पार्टी की महिला नेता रेणु देवी को दिया। अब इस गुस्से में मदन जायसवाल इतने आगबबूला हुए कि उन्होंने भाजपा ही छोड़ दी। भाजपा छोड़ने के बाद मदन जायसवाल, लालू यादव की पार्टी राजद में शामिल हो गए, राजद में शामिल होते ही उन्होंने बेतिया विधानसभा क्षेत्र से अपने बेटे संजय जायसवाल के लिए टिकट हासिल कर लिया। तो इस तरह 2005 के फरवरी में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में संजय जायसवाल ने बेतिया से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन, किस्मत उनके साथ नहीं रही। भाजपा ने रेणु देवी को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव रेणु देवी ही जीती। राजद के संजय जायसवाल पांचवें स्थान पर चले गए, और उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर भी भाजपा संगठन के अगले अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल के रिपोर्ट होने की संभावना सबसे अधिक है। परंतु भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि क्रिकेट की ही भाँति अनिश्चितताओं से भरी हुई है। आखरी गेंद तक अर्थात् घोषणा होने के अंतिम पलों तक फैसले बदल जाते हैं। इसलिए हम यहां और नामों की चर्चा कर देना चाहते हैं जिसकी चर्चा अध्यक्ष के तौर पर हो रही है।

संजीव चौरसिया प्रदेश अध्यक्ष की रेस में दूसरे स्थान पर हैं।

संजय जायसवाल के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी का नाम आता है तो वह है अति पिछड़ा समाज से आने वाले भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद के पुत्र, वर्तमान में दीधा के विधायक और पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजीव चौरसिया। इनका परिवार पुराना भाजपाई रहा है और यह खुद भी भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर प्रदेश महामंत्री दायित्वों का सफल नेतृत्व किया है। इनके दमदार पक्ष की बात करें तो केंद्र स्तर के नेताओं से सीधे संपर्क में रहते हैं, स्वभाव काफी सरल है कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जुड़ाव रखते हैं। और अति पिछड़ा समाज यदि इनकी अच्छी पैठ है। परंतु इनकी कमज़ोर पक्ष की बात करें तो भाजपा संगठन में रहते हुए इनके नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और ना ही दीधा के विधायक के तौर पर भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है।

☞ एमएलसी जनक चमार की भी चर्चा जोरों पर :- मायावती के पार्टी बसपा से



प्रमोद चंद्रवंशी

विधायक के तौर पर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गोपालगंज से पूर्व सांसद जनक चमार जी भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। संगठन में प्रदेश महामंत्री तक के दायित्व में रहे हैं और नित्यानंद राय के काफी करीब माने जाते हैं इसलिए इनकी भी चर्चा जोरों पर है।

☞ सीमांचल के प्रदीप सिंह पेश कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की मजबूत दावेदारी :- आपको याद होगा बिहार में गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह ने सर्वप्रथम सीमांचल के बोटरों को साधने के लिए बड़ी रैली की थी जिसमें प्रदीप सिंह ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। अररिया से दूसरी बार सांसद अति पिछड़ा समाज के गणीता जाति से आने वाले प्रदीप सिंह की सीमांचल में मजबूत पकड़ मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इन के माध्यम से सीमांचल के बोटरों को साध सकती है इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इनकी दावेदारी भी कम नहीं आंकी जा सकती है। हालांकि प्रदेश स्तर पर सांगठनिक अनुभव का अभाव है फिर भी विवेक ठाकुर के करीबी नामों में प्रदीप सिंह का नाम स्पष्ट रूप से आता है।

☞ प्रमोद चंद्रवंशी भी हैं प्रदेश अध्यक्ष के कतार में :- विद्यार्थी परिषद में कॉलेज मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तक एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री से लेकर वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष तक के दायित्व का निर्वहन करने वाले प्रमोद चंद्रवंशी भी प्रदेश अध्यक्ष की कतार में खड़े हैं।

☞ अजय निषाद के नाम की भी लगाई जा रही हैं अटकलें :- बोचांहा चुनाव के समय कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद के भी नामों की अटकलें लगाई जा रही थीं परंतु वर्तमान में इनके नाम की सहमति नहीं बन पाई है। ●



जातिगत उठागणना ओबीसी पट दलीय दार्शनीति!

गुरु नीतीश, तेजस्वी को दे रहे सीएम कुर्सी की ट्रेनिंग

● अमित कुमार

बी

जेपी को छोड़ आरजेडी के साथ सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद अटकले लगाई जाने लगीं कि नीतीश जल्द ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर देश की राजनीति में चले जाएंगे। पिछले महीने नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया कि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे। 2025 का चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हालांकि, इससे यह भी साफ हो गया कि तेजस्वी की ताजपोशी 2025 से पहले नहीं होगी। लालू यादव के छोटे बेटे अभी भले ही डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए थोड़ा और शासनिक अनुभव लेना चाहिए। वही जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। अब वे तेजस्वी को धीरे-धीरे सीएम का रोल समझा रहे हैं। यहां तक कि उनकी फील्ड ट्रेनिंग भी वे करवा रहे हैं। इसकी एक झलक वैशाली में समाधान यात्रा के दौरान दिखी। तेजस्वी यादव पहली बार नीतीश कुमार की

समाधान यात्रा में शामिल होने वैशाली पहुंचे। इस दौरान भीड़ का अभिवादन करते हुए नीतीश ने तेजस्वी को अपने साथ रखा। यह तेजस्वीर सियासी हल्कों में चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी चंपारण से 5 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत की थी। वही जब उनकी यात्रा वैशाली जिले में पहुंची, इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लिया। नीतीश और तेजस्वी ने गोरोल के हरशेर

में गुलाम रसूल साह वारसी के मजार पर माथा टेका और चादर चढ़ाई। इसके बाद जगदंबा स्थान पर माता के दर्शन और पूजा-अर्चना की। इसके बाद दोनों भगवानपुर के हुसैनाखुर्द पंचायत में पहुंचे, तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई। नीतीश ने अपनी कार से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। उनकी पिछली सीट पर तेजस्वी बैठे थे, उन्होंने भी बाहर निकलकर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

गोरतलब है कि तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री का काम समझाने में लगे हैं। दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठकों में नीतीश कुमार खुद नहीं गए, बल्कि तेजस्वी को भेजा। 17 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश की जगह तेजस्वी शामिल हुए थे। इसके बाद 30 दिसंबर को कोलकाता में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई गंगा परिषद की बैठक में भी तेजस्वी यादव ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया। दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भस्मासुर करार दिया है। पीके ने यह भी बताया कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों 2025



राजनीति



उपेन्द्र कुशवाहा

के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सरकार और उसका सीएम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यह सोची समझी रणनीति है। उन्हें तेजस्वी यादव से कोई प्रेम नहीं है और न ही उनके फैन हैं। बल्कि वे अपनी वाहवाही के लिए 2025 में आरजेडी का सीएम चाहते हैं। बिहार में जनसुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने मोतिहारी में मंडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इसलिए आरजेडी के नेता (तेजस्वी यादव) को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बिहार में फिर से जंगलराज आ जाए। इसके बाद जनता कहे कि इससे अच्छा तो नीतीश कुमार ही थे। नीतीश को पता है कि

2025 में उनकी विदाई तय है। इसलिए वे सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। पीके ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई अच्छा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन गया तो लोग कहेंगे कि बदिया हुआ, नीतीश से छुटकारा मिल गया। मगर आरजेडी का कोई नेता सीएम बना तो लोग कहेंगे कि इससे बदिया तो नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार को तेजस्वी से कोई प्रेम नहीं है। यही उनकी पॉलिटिक्स है कि 2025 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और भस्मासुर (तेजस्वी यादव) को जनता के सिर पर बैठाकर चले जाओ। फिर बिहार की जनता भोगे, देखे और कहे कि याद करे कि इससे बदिया तो पहले वाला ही था। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति पूरी इसी पर चली है कि आरजेडी के समय में स्थिति बहुत खराब थी, हमने उसे बेहतर किया। यानी कि नीतीश के टाइम में कम खराब है। नीतीश यह दावा ही नहीं करते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं। वे खुद ही कह रहे हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। उन्होंने दावा किया कि बिहार देश का सबसे अमीर राज्य बन गया या बनने वाला है।

इधर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बिहार के सत्ताधारी दलों आरजेडी और जेडीयू के बीच घमासान मच गया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद



जगदानंद सिंह

से पीएम बनेंगे। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार किसी व्यक्ति के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि जनता की कृपा से पीएम बनेंगे। जेडीयू नेता उपेन्द्र कुशवाहा से बातचीत में कहा कि जगदानंद सिंह कुछ कह देते हैं। कभी कभार, उनको बातों की अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या लालू यादव की कृपा से नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, तो कुशवाहा ने कहा—नहीं। नीतीश कुमार किसी व्यक्ति के कहने से पीएम नहीं बनेंगे, बल्कि हिंदुस्तान की जनता की कृपा से प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाती है। हालांकि, सहयोग सभी का रहता है। बता दें कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष





जगदानंद सिंह ने कहा था कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का देश की राजनीति में अहम योगदान रहा है। उनके आशीर्वाद से ही एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन पाए थे। अब उन्होंने नीतीश कुमार को भी आशीर्वाद दे दिया है। वे लालू के आशीर्वाद से पीएम बनेंगे। दूसरी ओर, उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू में जारी खींचतान और बढ़ने के आसार हैं।

बहरहाल, बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद वैशाली के हरशेर गांव में शिवशरण पासवान और मनोज पासवान के घर के पास के खंभे पर 01 लिखवाकर 14 दिनों तक चलने वाले इस सर्वेक्षण का विधिवत आगाज कराया। इसे नीतीश सरकार और प्रशासन ने खास तैयारी की है। ये पूरी प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में राज्य के सभी मकानों की संख्या गिनी जाएगी। और फिर दूसरे चरण यानी मार्च से सभी जातियों, धर्मों के लोगों से सर्वधित आंकड़े जुटाए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया मई 2023 तक पूरी हो जाएगी। बिहार में हो रही जातीय जनगणना का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए अपने आकस्मिक कोष से पूरा खर्च करेगी। सर्वे के लिए सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है। और करीब 2 लाख कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। बता दें कि इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सर्वे में पंचायत से जिला स्तर तक आंकड़ों को जुटाया जाएगा। इसे एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए डिजिटल रूप से एकत्र किया जाएगा। ऐप में जगह, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, उनके पेशे और सालाना आय के बारे में सवाल होंगे। जातीय गणना कर्मियों में शिक्षक, आंगनबाड़ी, मनरेगा

या जीविका कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कवायद पटना जिले के कुल 12,696 प्रखंडों में की जाएगी। वही सीएम नीतीश कुमार ने जातीय गणना को लेकर कहा कि ये सर्वेक्षण न केवल राज्य की वर्तमान जनसंख्या की गणना करेगा बल्कि हर जाति की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाएगा। इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए। हम सबका विकास चाहते हैं। इस प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को इस उद्देश्य के लिए ठीक से प्रशिक्षित किया गया है। सीएम ने कहा कि यह कवायद न केवल देश के विकास के लिए फायदेमंद साबित होगी बल्कि समाज के हर वर्ग का उत्थान करेगी। सनद् रहे कि केंद्र की ओर से जातीय गणना की मांग को खारिज करने के बाद राज्य सरकार को अपने दम पर इसे करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिहार विधानसभा ने जातीय गणना के लिए पहले भी दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित



नीतीश कुमार

किया था। केंद्र से इस पर विचार करने का अनुरोध किया था। पिछले साल अगस्त में, नीतीश की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मांग पर गौर करने के अनुरोध के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि विहार की राजनीति ओबीसी के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है, बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही हैं। बीजेपी के समर्थन से बिहार सीएम बनने के बावजूद नीतीश कुमार का जातीय गणना के मुद्दे पर मुखर रहने का मकसद बीजेपी के ओबीसी राजनीति को काउंटर करने का प्लान है। नीतीश ओबीसी राजनीति को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त यह अपने चरम पर है। बीजेपी भी इस बात को समझती है, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सफल चुनावी अभियानों को देखा है। ओबीसी में प्रभुत्व वाली जातियों के बदले जिनका प्रभुत्व नहीं रहा है, उन्हें तक्जो देना बीजेपी की अहम चुनावी रणनीति रही है। बिहार में पार्टी ने जिन दो नेताओं को दो उप-मुख्यमंत्री बना रखा है, वे भी ओबीसी हैं, ऐसे में नीतीश कुमार की कोशिश जातीय गणना कराकर बीजेपी के समीकरण को तोड़ने और ओबीसी जातियों को एक बड़ा सियासी संदेश देने का है। वही ओबीसी वर्ग को लगता है कि उनका दायरा बढ़ा है, जातिगत गणना में आरक्षण की 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। बिहार के सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए जातीय गणना की मांग तेज हुई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान वैशाली में घोषणा किया कि बिहार में जातीय गणना के बाद आर्थिक जनगणना कराई जाएगी। सीएम नीतीश ने कहा कि जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा, तब आर्थिक आधारित गणना भी कराई जाएगी। ताकि जिससे सही-सही पता चल सके कि कौन अमीर है और कौन गरीब है।



गैरतलब हो कि जातीय गणना के पहले दिन ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर पूर्व में नीतीश कुमार का साथ देने वाली बीजेपी ने अब सरकार को धेरा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जातीय गणना कराकर बिहार को जातियों में बांटना चाहते हैं और फिर उन्माद पैदा करना चाहते हैं। जाति आधारित गणना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि हम आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। आज 75 साल की आजादी में अब तक क्यों जातीय जनगणना की बात नहीं हुई थी। 1931 के बाद देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई। इसके सवालों का नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जातीय उन्माद पैदा करके नरसंहार कराया। अब नीतीश कुमार भी उनके नक्शेकदम पर आगे बढ़ रहे हैं। विजय सिन्हा ने नीतीश से कहा कि आप जातीय गणना कराना चाहते हैं, तो जरूर कराइए। मगर 500 करोड़ रुपये खर्च करके, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित और कमज़ोर तबके को मिल पाएगा। नीतीश सरकार बेरोजगारों पर लाठियां बरसा रही है। अध्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय नीतीश उन्माद पैदा करने के लिए जाति आधारित गणना करवा रही है। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश दोनों 32 साल से बिहार की सत्ता में रहे। मगर इन्हें साल जाति आधारित गणना क्यों नहीं करवाई। अब बिहार के विकास की गति बढ़ानी है तो अब दोनों भाई बिहार के बातावरण को दृष्टि करना चाहते हैं, बिहार को जातियों में बाटकर उन्माद फैलाना चाहते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश

सरकार को जाति आधारित गणना के बजाय आर्थिक जनगणना करवानी चाहिए ताकि समाज को तोड़ने से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीएम को पहले पूरा विजय बनाना चाहिए। 5 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं उन्होंने क्यों पलायन किया, जिलेवार उनकी लिस्ट बनवानी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

बिहार में जाति आधारित गणना यानी जातीय गणना शुरू होते ही बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ जातियों की गणना करवा रहे हैं, उपजातियों की गिनती क्यों नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की उपजाति की संख्या नालंदा में 5 फीसदी भी नहीं है, इसलिए वे पूरे बिहार में उपजातियों की गणना नहीं करवा रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल

ने प्रेस वार्ता कर जातीय गणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज में दांगी को उपजाति नहीं मानेंगे तो क्या उसे एक अलग ही जाति मानेंगे? बनिया समाज में 65 उपजातियां हैं तो क्या उसे एक वैश्य समाज में ही मानेंगे या 65 उपजातियों में मानेंगे। नीतीश कुमार को एक बार सामने आकर सभी दलों से बताना चाहिए कि वे उपजाति की गणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार उपजाति की गणना इसलिए नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि नालंदा में कुर्मी समाज में उनकी उपजाति की संख्या महज 5 फीसदी भी नहीं है। इसी कारण वे पूरे बिहार में उपजातियों की गणना नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने नीतीश से जातीय गणना के हरियाणा मॉडल को लागू करने की भी मांग की है। संजय जायसवाल ने कहा कि हरियाणा ने अपनी जनगणना को दो भागों में बांटा है, एक परिवार पहचान पत्र और दूसरा अंत्योदय सरल, उसमें सभी की पहचान लॉक है। जब कोई व्यक्ति 60 साल का होता है तो वह एक पोर्टल पर आवेदन करके पेंशन ले सकता है, कोई पिछड़े वर्ग का बच्चा 10 साल का होता है तो वह उसी पोर्टल पर आवेदन करके स्कॉलरशिप पा सकता है। इसका सबसे बड़ा यही लाभ है।

वही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की जातीय गणना को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। नीतीश कुमार राजनीति करने के लिए जातीय गणना करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना जनगणना के ही मैं बता देता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोग सबसे गरीब और पिछड़े हैं, उनकी स्थिति सुधार दीजिए। इसमें जनगणना की क्या जरूरत है। रोज ही सर्वे आ रहे हैं। पीके ने कहा है कि जातीय गणना से समाज में उन्माद फैलेगा जिसे नीतीश कुमार अनदेखा कर रहे हैं। जाति आधारित गणना समाज जोड़ने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए है। दरअसल, जातीय जनगणना का वैधानिक आधार है ही नहीं। जातीय गणना का फायदा गिनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह विस्तार से उदाहरण देकर बताना चाहिए कि इसका वैधानिक आधार क्या है? उन्होंने यह भी पूछा कि इससे जनता का क्या और कैसे विकास होगा? प्रशांत किशोर ने कहा कि जातीय गणना समाज में सबसे निचले पायदान पर स्थित लोग और नीचे चले जाएंगे। उनका कोई भला नहीं होगा। उलटे, समाजवाद के नाम पर बिहार का समाज अलग अलग खंडों में बंट जाएगा। नीतीश जी का मकसद भी यही है। बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है।



डॉ० चंद्रशेखर सिंह



विजय सिंहा

बताते चले कि बिहार से पहले अब तक सिर्फ दो राज्यों में जातिगत जनगणना हुई है। सबसे पहले 2011 में राजस्थान में लोगों की गिनती जाति के आधार पर की गई। हालांकि, आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद की सरकार ने भी इस रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बाद कर्नाटक में साल 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो इसका नाम बदलकर 'सामाजिक एवं आर्थिक' सर्वे कर दिया गया। राज्य सरकार ने इसपर 150 करोड़ खर्च किए। साल 2017 में कर्णाटक समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। वही कांग्रेस के लिए यह कदम सही साबित नहीं हुई। सरकार ने अपना बहुमत खो दिया था। कांग्रेस अपनी एक तिहाई सीटें भी नहीं बचा सकी थी। 'सामाजिक एवं आर्थिक' सर्वे के नाम पर शुरू हुई जातिगत जनगणना की कवायद विवादों में घिर गई। अपने समुदाय को ओबीसी या एससी/एसटी में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए यह सर्वे बड़ा मौका बन गया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराए। नतीजा यह हुआ कि एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और वॉकलिंग जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। सिद्धरमैया ने यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि जातिगत गणना कराने के पक्ष में तरक्की ये है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी



संजय जायसवाल



प्रशांत किशोर

होने का अनुमान लगाया था। वही जिस तरह से दो राज्यों ने जातिगत रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया। ऐसे में बिहार को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। रिपोर्ट फाइलों से बाहर नहीं निकली। बिहार में फिलहाल महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बिहार में भी रिपोर्ट आगर राज्य सरकार के अनुकूल नहीं हुए तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा?

बहरहाल, जिस तरह से बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर पांच पसार रहा है वैसे में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस मुहिम पर रोक लगा दी है। बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की बिहार सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई कराने के लिए



लालू प्रसाद यादव

सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को होगी। वही बता दें कि जाति आधारित गणना बिहार सरकार के एंजेंडे में शामिल हैं। राज्य में जाति जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार की 6 जनवरी, 2022 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश कुमार ने अधिवक्ता बरुन कुमार सिन्हा और अभिषेक के माध्यम से दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार के उप सचिव द्वारा जारी 06/06/2022 की अधिसूचना पर कार्रवाई का कारण सामने आया है, जिसमें सरकार के जातिगत जनगणना कराने के निर्णय को मीडिया और जनता को सूचित किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार राज्य का फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन, असंवैधानिक और कानून के अधिकार के बिना है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में 200 से अधिक जातियां हैं और उन सभी जातियों को सामान्य श्रेणी, ओबीसी, ईबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में बांटा गया है। याचिका के अनुसार, बिहार राज्य में 113 जातियां हैं, जो ओबीसी और ईबीसी के रूप में जानी जाती हैं, आठ जातियां उच्च जाति की श्रेणी में शामिल हैं। वहीं, लागभग 22 उप-जाति अनुसूचित श्रेणी में शामिल हैं और 29 अनुसूचित जातियां हैं। याचिका में कहा गया है कि बिहार राज्य के अवैध फैसले के लिए अलग-अलग व्यवहार को रेखांकित कराने वाली अधिसूचना अवैध, मनमाना तर्कहीन और असंवैधानिक हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अपील को रद्द कराने के लिए एक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 6 जनवरी, 2022 की अधिसूचना और संबंधित प्राधिकरण को जाति गणना कराने से बचने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि यह भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। ●

चचा शिवपाल की हुई वापसी तो करीब आने लगे पुराने सगे-संबंधी

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार)

स

माजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव काफी बदले-बदले नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल तक जो अखिलेश किसी की नाराजगी की चिंता नहीं करते थे, अब वह अपना परिवार और 'कुनब' बचाने के लिए जहोजहद करते नजर आ रहे हैं। सपा की खोई हुई ताकत हासिल करने के लिए रुठों को मनाया जा रहा है तो बिछड़ों को पार्टी में वापस बुलाया जा रहा है। लम्बे समय के बाद चचा शिवपाल यादव एक बार फिर भीजे अखिलेश के खेबनहार बन गए हैं। उनका चचा के प्रति विश्वास जगा तो मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधान सभा सीट सपा के खाते में आ गई। खतौली विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी से विक्रम सिंह सैनी विधायक चुने गए थे, जिनकी मुजफ्फरनगर दंगों में सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्या रह हो गई थी। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी के परिवार पर ही भरोसा जताया था और उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा था। राजकुमारी सैनी का सामना सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया से हुआ था और उन्हें मदन भैया से करीब 23 हजार वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। अखिलेश यादव ने खतौली विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोक दल को देकर एक बार फिर जयंत चौधरी पर भरोसा जताया था, जिस पर वह खरे उतरे। इसके बाद से सपा-रालोद गठबंधन के बीच का विश्वास बढ़ गया है। यह और बात है कि सपा नेता अजय खान के गढ़ रामपुर में सपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा।

बात मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की कि जाए तो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत के बाद अखिलेश यादव 2024 के आम चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। चचा शिवपाल के बीच दूरियां मिटने के बाद चचा के कहने पर अखिलेश यादव अब पार्टी के असंतुष्टों और पूर्व सहयोगियों को फिर से साथ लाने में लग गए हैं। ऐसे क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि सपा अगर उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में ठीक-ठाक प्रदर्शन करती है तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले

कुछ भाजपा विरोधी दल सपा के पीछे लामबंद हो सकते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल की जबरदस्त जीत के बाद बदायू के पूर्व विधायक आबिद रजा जहां पार्टी में दोबारा शामिल हो गए, वहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा के प्रति अपने तेवर में नरमी के संकेत देते हुए कहा, "शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो हमारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फिर से बातचीत हो सकती है।"

बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि मैनपुरी उपचुनाव और यादव परिवार की एकजुटता ने भाजपा के समानांतर भविष्य तलाशने वालों की उम्मीद जगा दी है और अगर सपा ने निकाय चुनावों में ठीक-ठाक प्रदर्शन



किया तो लोकसभा चुनावों के लिए छोटे दल फिर सपा के साथ आने को आतुर होंगे। इसके लिए सबसे पहले अखिलेश और शिवपाल की निकटता को निकाय चुनाव की कपोरी पर खरा उतरना होगा और इस चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय हो जाएगी। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा, महान दल, अपना दल (कमेरावादी) और जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) जैसे छोटे दलों ने सपा नीत गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। अपना दल (कमेरावादी) को छाड़कर इनमें से बाकी सभी दलों ने विधानसभा चुनाव के बाद सपा से दूरी बना ली थी, लेकिन मैनपुरी में सपा की जीत के बाद इन दलों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है।

मैनपुरी संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं भाजपा

प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को 2.88 लाख से अधिक मतों से हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम ने मैनपुरी से करीब 90 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीता था। माना जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच मतभेद समाप्त होने और यादव परिवार की एकजुटता ने ही सपा के पक्ष में माहौल बनाया। राजनीतिक जानकार यही दावा कर रहे हैं कि अगर यादव परिवार की एकजुटता बनी रही तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ही भाजपा के खिलाफ मुख्य मुकाबले में नजर आएगी। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रह चुके राजभर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सपा में संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। इस सिलसिले में जब राजभर से बातचीत की गई तो उन्होंने दो टूक कहा, बात करने में क्या दिक्कत है। कोई खेत-मेड़ का झगड़ा तो है नहीं, राजनीति में कौन किसका दुश्मन है। अपनी बात को बल देने के लिए राजभर बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कश्मीर में भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा और बसपा के बीच हुए गठबंधन का उदाहरण भी देते हैं। राजभर ने दावा किया है कि हम निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी न किसी से गठबंधन जरूर करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या सपा के किसी नेता ने सुभासपा से हाथ मिलाने की पहल की है, उन्होंने कहा कि अभी किसी ने कोई पहल नहीं की है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव के बाद हुए विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने से जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) के अध्यक्ष डॉ. संजय चौहान सपा से खफा हो गए थे, लेकिन अब वह फिर पार्टी के साथ आ गए हैं। 2019 में सपा के चिह्न पर चौदोली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके डॉ. चौहान ने से बातचीत में स्वीकार किया, "विधान परिषद के चुनाव में मौका न मिलने से सपा से थोड़ी दूरी हो गई थी, लेकिन अब हम अखिलेश जी के साथ हैं और निकाय चुनाव में सपा का समर्थन करेंगे।"

उधर, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य कहते हैं कि हम लोग (छोटे दल) मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं और मुख्य खिलाड़ी (बड़े दल) अभी पते नहीं खोल रहे हैं। ऐसे में

हम किसके साथ जाएंगे, इसे लेकर खूब तुकड़ेबाजी चल रही है।” अखिलेश के साथ दोबारा तालमेल बैठाने की संभावनाओं पर मौर्य ने कहा, “देखिए, अखिलेश यादव से ही नहीं, भाजपा से, कांग्रेस से, बसपा से, सभी से गठबंधन की संभावनाएं हैं। जब हम अपनी बदौलत एक भी सीट जीत नहीं सकते तो किसी न किसी का सहारा तो लेंगे ही। अब सहारा कौन देगा, यह उन पर (बड़े दलों पर) निर्भर करता है।” महान दल के नेता ने कहा, “पहल बड़े दलों को करनी है और अगर कोई हमें बुलाता ही नहीं है तो हम गठबंधन के लिए तैयार होकर भी क्या करेंगे।” उन्होंने संकेत

दिया कि वह मौके का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, “सपा ही भाजपा की एकमात्र विकल्प है। अखिलेश जी सक्षम है। लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि देर से ही सही, लेकिन बहुत से लोग सपा में आएंगे। हालांकि, जब ओमप्रकाश राजभर से गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो चौधरी ने कहा कि उनके बारे में अखिलेश जी ही तय करेंगे।

खैर, सभी दलों की निकाय चुनाव पर नजर है तो सियासी गलियारों में अटकलें लगाई

जा रही हैं कि राजभर जैसे छोटे दलों के नेता निकाय चुनाव में सपा की स्थिति का आकलन करेंगे और परिणाम के हिसाब से ही 2024 के चुनाव के लिए अपनी दिशा तय करेंगे। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, लेकिन निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण का के खिलाफ कुछ लोग हाइकोर्ट गये हैं, जिस कारण अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। राज्य में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में महापौर, अध्यक्ष और सभासदों के चयन के लिए मतदान होना है।●

सियासत का कारोबार और कारोबार की सियासत

• विश्वजीत शेखर राय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई में उद्घागपतियों और सिनेमा जगत के दिग्गजों से मुलाकात की खबरें आजकल चर्चा का केन्द्र बनी हुई हैं। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है एवं लोकसभा की सर्वाधिक अस्सी सीटें होने के कारण देश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह इसकी महत्वा ही है कि 2014 में नेत्रन मोरी को उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना पड़ा। इतने महत्वपूर्ण सूबे में भाजपा पिछले दो विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती है और योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। उत्तर प्रदेश के साथ अपनी समस्याएं रही हैं। यह एक बड़ा राज्य है और लैंड-लॉक्ट होने के कारण कभी भी व्यापार का गढ़ नहीं रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात की तरह यहाँ व्यापार की संभावनाएं कभी विकसित नहीं हुईं। बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे आईटी शहर भी यहाँ के राजनेता विकसित नहीं कर पाएं। गांगा-यमुना के क्षेत्र और हिमालय के तराई क्षेत्र में अवस्थित इस सूबे को कृषि प्रधान ही कहा जाता है लेकिन यहाँ के किसानों की स्थिति पंजाब और हरियाणा के किसानों जैसी नहीं है। इन सभी समस्याओं के साथ इस क्षेत्र में व्यापारों के विस्तार में कानून और न्याय व्यवस्था भी एक बाधा की तरह रही है। यह सभी समस्याएं किसी भी सूबे में कारोबारियों की रुचि और निवेश को प्रभावित करती है।

पहले बात करते हैं सियासत के कारोबार की, पिछले अनेक मुख्यमंत्रियों की तरह ही योगी आदित्यनाथ को भी यही पिछड़ा



उत्तर प्रदेश विरासत में मिला। उत्तर प्रदेश में ‘लॉ एंड ऑर्डर’ ठीक रखने वाले मुख्यमंत्रियों को ही मजबूत मना गया है क्यूंकि विकास यहाँ कभी सफलता और मजबूती का पैमाना बन ही नहीं पाया। योगी ने भी अपने आप को मजबूत दिखाने और प्रशासन पर अपना कण्ट्रोल स्थापित करना अपनी प्राथमिकता समझी और यह जरूरी भी थी क्यूंकि योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी चक्रवृद्ध में थी। हर स्तर पर पर उनके सम्मुख अलग-अलग चुनौतियां थीं। गोरखपुर में शिवप्रताप शुक्ल को केंद्रीय मंत्री बनाकर उनकी अपनी पार्टी ने गोरखपुर में उनके एकाधिकार को चौलेन्ज किया। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ओवीसी के काढ़वर नेता बन चुके थे और लखनऊ की कुर्सी के दावेदार के रूप में भी कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। राष्ट्रीय फलक पर भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों में देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा और बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी

मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पहचान बनानी थी। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ इन सब बाधाओं को अपनी सियासी समझ बुझ से पार कर चुके हैं।

2014 के बाद भारत की राजनीति में आंकड़ों और व्यापार का गणित महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए इस कार्यकाल में योगी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और व्यापार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। वह जानते हैं कि देश को अगर उत्तर प्रदेश मॉडल दिखाई देने लगा तो उनकी दिल्ली कि राह आसान हो जाएगी। ‘लॉ एंड ऑर्डर’ और एक्सप्रेस वे का नेटवर्क तभी सार्थक हो पायेगा जब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में ‘निवेश’ कि ऊर्जा से शकारोबार का बल्ब प्रकाशित हो। यह कारोबार की सियासत भी आसान नहीं है लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस कसरत का ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ में कितना प्रभाव पड़ता है और सूबे में कारोबार की दशा कितनी बदलती है। इस सियासत के ही बहाने दशकों बाद उत्तर प्रदेश में उद्योगों की वापसी की उम्मीद जग रही है यह महत्वपूर्ण है।

अगर हम अगले महीने होने वाले ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ की बात करे तो इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्धारित 17 ट्रिलियन रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कहा जा रहा है कि प्रदेश ने चार सप्ताह पहले ही प्रस्तावित निवेश लक्ष्य का 70 प्रतिशत हासिल कर लिया है। अब तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से 12 ट्रिलियन रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 16 देशों से 7 ट्रिलियन रुपये के वैश्विक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि योगी की मुंबई यात्रा के दौरान लगभग 5 ट्रिलियन रुपये के घरेलू निवेश प्रस्ताव प्राप्त है।●

(लेखक एक स्तंभकार है)

क्या योगी को 2024 के लिए पीएम फेस बनाने का समय आ गया है?

● अभिमनोज

चा हे एकतरफा मीडिया कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी का सियासी जादू खत्म हो चुका है! पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हुए ज्यादातर बड़े चुनावों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाबजूद कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, लिहाजा दक्षिण भारत में तो वैसे भी बीजेपी के लिए कोई खास गुंजाइश नहीं है और उत्तर भारत में सियासी खरीद-फरोख, जोड़-तोड़ से बनी सरकारों को हटा दें, तो बीजेपी का भगवा रंग बहुत कम क्षेत्रों में नजर आएगा? लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जहां नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल क्रेज कम हुआ है, वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक आकर्षण बढ़ रहा है! देश में हाल ही हुए चुनावों और उपचुनावों के नतीजे बताते हैं, कि गुजरात को छोड़कर कहीं भी नरेंद्र मोदी का क्रेज नहीं बचा है? चुनाव से पहले तीन सत्ताएं- हिमाचल, एमसीडी और गुजरात, बीजेपी के पास थी जिनमें से केवल गुजरात की सत्ता बची है, मजेदार बात यह है कि मोदी के गुजरात में भी योगी का तगड़ा क्रेज है और योगी मॉडल चर्चा में है! इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सियासी ठगी के चलते जनता में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कोई खास उत्सुकता नहीं बची है, वैसे तो पीएम मोदी ने अपनी पार्टी में सारे प्रतिद्वंद्वियों को किनारे कर दिया था, लेकिन बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल क्रेज बढ़ता जा रहा है, लिहाजा,



2024 में नरेंद्र मोदी के लिए योगी आदित्यनाथ बड़ी चुनौती हो सकते हैं? हालांकि, बीजेपी में पीएम उम्मीदवार वही होगा, जिसे संघ चाहेगा, इसलिए यदि संघ ने योगी को पसंद कर लिया तो नरेंद्र मोदी को लालकृष्ण आडवाणी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा! बीसवीं सदी में श्रीराम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी के संस्थापक और प्रमुख नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी सबसे बड़े पॉलिटिकल हीरो बनकर उभरे थे, लेकिन एककीसवीं सदी के पहले दशक के बाद लालकृष्ण आडवाणी की लगातार नाकामयाबी के चलते उनके बजाए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी सबसे बड़े पॉलिटिकल हीरो बन गए और अब यह सियासी समीकरण भी तेजी से बदल रहा है, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे

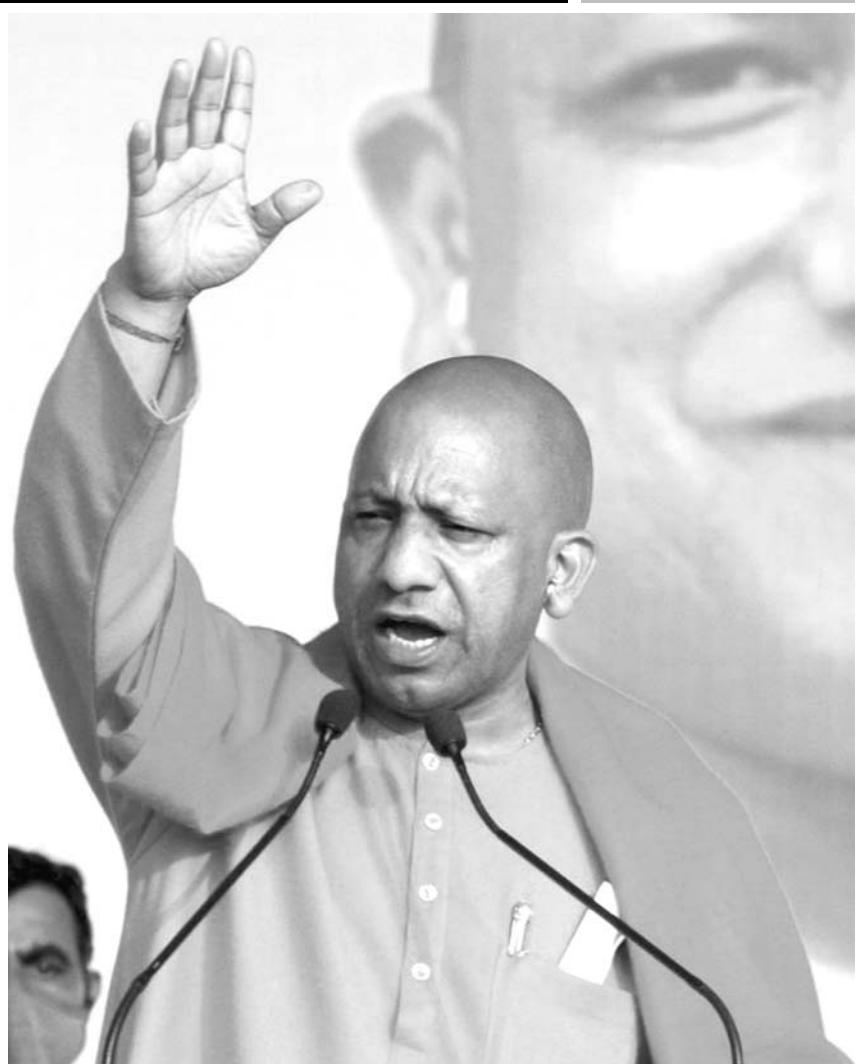
बड़े पॉलिटिकल हीरो बनते जा रहे हैं? बीजेपी समर्थकों के बीच जो पॉलिटिकल क्रेज 2014 में मोदी का था, आजकल योगी का नजर आ रहा है, तो क्या.... 2024 में योगी पीएम फेस होगे? लगता तो यही है, क्योंकि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की राजनीतिक ताकत केवल सीएम योगी में नजर आ रही है! बीजेपी के समर्थकों के बीच ही नहीं, आप जनता में भी मोदी का बो आकर्षण नहीं रहा है कि अब जनता अच्छे दिन के दावे पर भरोसा कर सके?

मोदी-राज के इन आठ वर्षों में जनता ने जो दर्द प्रत्यक्ष महसूस किया है, उसे किसी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के दम पर खत्म नहीं किया जा सकता है! यह तो योगी का ही सियासी दम था कि यूपी चुनाव में वे फिर से जीत दर्ज करवाने में कामयाब रहे, वरना जनता की केंद्र की मोदी सरकार के प्रति नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती थी? लोग पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के रेट को लेकर बेहद खफा थे, तो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने सबको परेशान करके रख दिया था, ऐसे माहौल में भी योगी की शानदार सफलता आश्चर्यजनक है! बीजेपी के पास करीब आधा दर्जन ही ऐसे राज्य हैं, जहां से बहुमत की ज्यादातर लोकसभा सीटें आई हैं और उनमें भी यूपी सबसे प्रमुख है, लिहाजा पीएम मोदी के सियासी तौर-तरीकों, उपरेशों से उब चुकी जनता को यदि योगी जैसा विकल्प मिला तो ही 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव में



बहुमत की उम्मीद रख सकती है?

योगी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वे यूपी से हैं, जिसके दम पर केंद्र में सरकारें बनती रही हैं? इन पांच वर्षों में जहाँ सीएम योगी का सियासी कद बढ़ा है, वहीं, पीएम मोदी का समर्थन जनता में ही नहीं, बीजेपी समर्थकों में भी कम हुआ है, यही वजह है कि. ... योगी-योगी के नारे मोदी-मोदी पर भारी पड़ रहे हैं? योगी या मोदी! 2024 में कौन होगा बीजेपी का पीएम फेस? इस पर पल-पल इंडिया में लिखा था कि.... वर्ष 2014 में बीजेपी को नरेंद्र मोदी.... एक नया पीएम फेस मिला था, वह समय था.... बीजेपी के पॉलिटिकल सुपर स्टार रहे और पहली बार बीजेपी को केंद्र की सरकार तक पहुंचानेवाले लालकृष्ण आडवाणी की विदाई का और अब 2024 आ रहा है, जब पीएम मोदी की लोकप्रियता उतार पर है, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता शिखर पर है! इसीलिए.... बड़ा सवाल यही है कि- योगी या मोदी, 2024 में कौन होगा बीजेपी का पीएम फेस? जब तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पॉलिटिकल डायमंड रहे, लेकिन इन आठ वर्षों में उनकी वह चमक नहीं रही और आजकल वे पॉलिटिकल अमेरिकन डायमंड नजर आने लगे हैं? यही वजह है कि 2014 तक योगी, तब जिनका सियासी कद कुछ खास नहीं था, इस वक्त बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेता हैं! देखते हैं, इन आठ वर्षों में क्या-क्या बदलाव आए हैं.... एक- योगी की विश्वसनीयता बड़ी है, वे बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन काम करते रहते हैं, जबकि मोदी की अच्छे दिनों की सारी बड़ी-बड़ी बातें, सारे बड़े-बड़े दावे झूठे निकले हैं, आज उनकी इमेज सबसे झूठे प्रधानमंत्री की है! दो- योगी हिन्दुत्व का दिखावा



नहीं करते, बावजूद इसके, वे हिन्दुत्व की पहचान बन गए हैं, जबकि कभी देश में मुस्लिम योपी नहीं पहन कर लोकप्रिय हुए मोदी, विदेशों में मुस्लिम शाल भी ओढ़ लेते हैं, यही नहीं, सबसे ज्यादा मस्जिद और मजार पर जानेवाले प्रधानमंत्री का रिकार्ड भी मोदी के नाम ही है! तीन- मोदी सरकार की महरबानी से किसान आंदोलन, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते रेट, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी जैसे बड़े-बड़े मुद्दों के रहते भी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद योगी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं! चार- योगी दिन में कई बार कपड़े नहीं बदलते हैं और न ही उनकी ऐसे किसी प्रदर्शन में दिलचर्षी नजर आती है, बावजूद इसके.... भगवा धोती, लाखों के सुट-बुट पर भारी पड़ रही है! पांच- जहाँ मोदी केवल प्रचार पर केंद्रित हैं, वहीं योगी परिणाम पर ध्यान दे रहे हैं! सियासी सायानों का मानना है कि वर्ष 2024 में मोदी, उन्हीं की टीम की ओर से सत्ता से सेवानिवृत्ति की निर्धारित उम्र 75 वर्ष के एकदम करीब होंगे, मतलब 2024 में बीजेपी को नए पीएम फेस की जरूरत रहेगी! ●



● अजय कुमार

सु

प्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट काफी समय से अपने तमाम फैसलों के दौरान केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता लाने के लिए कह रहा था। यह बात तो सबको पता थी, लेकिन केन्द्र कानून बनाने की राह क्यों नहीं पकड़ रही थी। यह बात कम ही लोगों को समझ में आ रही थी। परंतु राज्यसभा में भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद की ओर से निजी स्तर पर समान नागरिक संहिता विधेयक(यूसीसी) प्रस्तुत करके समान नागरिक संहिता पर गरम बहस छेड़ दी है। यूसीसी का राज्यसभा में जैसा विरोध हुआ, उसका औचित्य समझना कठिन है, क्योंकि हमारे संविधान में भी समान नागरिक संहिता को आवश्यक बताया गया था।। इसके बाद भी यूसीसी का विरोध यहीं बताता है कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता पर बहस करने के लिए भी तैयार नहीं। आखिर जिस समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, उस पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती और वह भी तब, जब निजी विधेयक पेश करने की एक परंपरा है? यह हास्यास्पद है कि कई विपक्षी सांसदों ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की पहल को संविधान विरोधी बता दिया। इसे अंधविरोध और कुर्तक के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

भाजपा के

राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 09 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्राइवेट मैम्बर के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का प्रस्ताव पेश किया। यानी राज्यसभा में यह विधेयक सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया है। बल्कि सांसद द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक पेश किए जाने के बाद भाजपा के रुख ने संकेत दिया है कि उनके सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जो बिल पेश किया उसका पार्टी मौन समर्थन है।

राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीजेपी की नजर 2024 के आम चुनाव पर है और सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा थी कि यह सदस्य का वैध अधिकार है। उच्च सदन के कई सदस्यों ने स्वीकार किया है कि सत्ता पक्ष अवसर की तलाश कर रहा है और जब सदन में विपक्ष की संख्या कम थी तब विधेयक पेश किया गया। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस कुछ सदस्यों को छोड़कर अनुपस्थित थी और संकेत दिया कि हो सकता है कि कांग्रेस बिल का विरोध नहीं करना चाहती हो। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 बनाकर उसमें कहा भी गया

है कि सरकार आगे चलकर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम करेगी, लेकिन मीणा की तरफ से लाए गए समान नागरिक संहिता बिल का विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस, सपा और ममता बनर्जी की तुण्डल कांग्रेस जड़बू ने बिल के खिलाफ आवाज उठाई, हालांकि बिल पेश करने की राह में वे रोड़े नहीं अटका सके।

उल्लेखनीय है कि कई चुनावों में यूसीसी भाजपा के घोषणापत्र में रहा है। जबकि निजी सदस्य का बिल 2020 से लंबित था, लेकिन पेश नहीं किया गया था। यूसीसी नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने के लिए एक प्रस्तावित कानून है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग या जैन अधिविन्यास की परवाह किए बिना लागू होगा। दरअसल, उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यूसीसी के पक्ष में अपनी हामी पहले जाहिर कर चुके हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यूसीसी के

कार्यान्वयन को सूचीबद्ध किया था, लेकिन पार्टी को राज्य में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

WHY INDIA NEEDS A
UNIFORM CIVIL CODE

उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड के निवासियों के निजी दीवानी मामलों को विनियमित करने वाले संबंधित कानूनों की जांच करने और कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। इसके तहत वर्तमान में प्रचलित कानूनों में संशोधन व सुझाव उपलब्ध कराना। साथ ही राज्य में विवाह, तलाक के संबंध में वर्तमान में प्रचलित कानूनों में एकरूपता लाने का मसौदा बनाना। राज्य में समान नागरिक सहिता के लिए मसौदा तैयार करना शामिल है।

बता दें कि विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक सहिता विधेयक निजी सदस्य द्वारा 09 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में पेश किया गया। कुल 63 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 23 मत इसके विरोध में पड़े। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और द्रमुक ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि बीजू जनता दल ने सदन से बॉक आउट कर दिया। यह ठीक है कि निजी विधेयक मुश्किल से ही कानून का रूप लेते हैं और हाल के इतिहास में तो किसी भी ऐसे विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन किसी भी सांसद को निजी स्तर पर विधेयक पेश करने का अधिकार है। जब ऐसे विधेयकों पर संसद में चर्चा होती है तो देश का ध्यान संबंधित विषय की ओर आकर्षित होता है और उस पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया तेज होती है। यदि भाजपा सांसद किरोड़ीमल मीणा के निजी विधेयक के जरिये यह काम होता है तो इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए?

निजी स्तर पर पेश किए गए समान नागरिक सहिता विधेयक पर राज्यसभा में व्यापक बहस इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि कई राज्य सरकारें इस सहिता के निर्माण की दिशा में सक्रिय हैं। जहां उत्तराखण्ड ने इसे लेकर एक समिति गठित कर दी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, वहीं गुजरात सरकार ने भी चुनाव में जाने के पहले ऐसा करने का वादा किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक सहिता के निर्माण की आवश्यकता जताई है। इन स्थितियों में आवश्यक केवल यह नहीं कि संसद में समान नागरिक सहिता को लेकर विस्तार से बहस हो, बल्कि यह भी है कि केंद्र सरकार इस सहिता का कई मसौदा सामने लाए, जिससे आम जनता के बीच भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़े। जब ऐसा होगा तो समान नागरिक सहिता को लेकर दुष्प्रचार की जो राजनीति हो रही है, उसकी काट करने में मदद मिलेगी। यह दुष्प्रचार बोट बैंक की



राजनीति के तहत और साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने के शरातपूर्ण इरादे से हो रहा है। इसका पता विपक्षी सांसदों के इस तरह के थोथे बयानों से चलता है कि समान नागरिक सहिता के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने से विविधता की संस्कृति को क्षति पहुंचेगी। यह निराद्वाट है, क्योंकि यह सहिता तो विविधता में एकता के भाव को बल देती। इसके साथ ही इससे राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलेगा।

उधर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक सहिता विधेयक को एक प्राइवेट बिल के तौर पर राज्यसभा में पेश किए जाने को निराशाजनक कदम बताया है। बोर्ड ने इस कदम को देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया है। बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि देश के संविधान का निर्माण करने वालों ने बहुत ही सोच समझ कर संविधान बनाया था। संविधान में हर वर्ग को अपने धर्म और अपनी संस्कृति के अनुसार जिंदगी गुजारने की इजाजत दी गई है। इसी सिद्धांत पर केंद्र सरकार ने आदिवासियों से समझौता भी किया था ताकि वह पूरे देश में अपनी विशेष पहचान के साथ इस देश के नागरिक बनकर रह सकें। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इनको कभी भी उनकी भाषा एवं संस्कृति से रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसी भरोसे के तहत देश में मुसलमान, ईसाई, पारसी और अन्य धार्मिक गुप्त अपने-अपने पर्सनल लौ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इन

सब पर समान नागरिक सहिता लागू करने का कोई फायदा तो नहीं होगा लेकिन इससे देश को नुकसान हो सकता है। इससे हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह देश की ज्वलतं समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करे। ऐसी बातों से बचे जो फायदे के बजाय नफरत पैदा करने वाली हों। बोर्ड महासचिव खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि भारत जैसा देश जहां दुनिया के सबसे ज्यादा आवादी बसती है और जो दूर सारे धार्मिक और सांस्कृतिक गुणों का संगम है, वहां समान नागरिक सहिता बिल्कुल भी सही नहीं है बल्कि यह नुकसानदेह साबित होगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट ने पहले अपने फैसलों के दौरान केंद्र सरकार से समान नागरिक सहिता लाने के लिए कहा भी है। इसके अलावा उत्तराखण्ड, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने इसे लागू करने के लिए रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटीया भी बनाई हैं। कांग्रेस और कई विपक्षी दल समान नागरिक सहिता लागू करने का विरोध कर रहे हैं। जबकि, बीजेपी हर बार इसे चुनावी एंडेंड में शामिल करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि समान नागरिक सहिता पर संसद में पेश प्राइवेट मेंबर बिल को मोदी सरकार और बीजेपी की तरफ से समर्थन मिल सकता है। हालांकि, इसे दो-तिहाई बहुमत से दोनों जगह पास कराना होगा। लोकसभा में ऐसा समर्थन तो मिल जाएगा, लेकिन राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए कई विपक्षी दलों की मदद लेनी होगी। ●

शराब के खेल में पुलिस और राजनेताओं की सांठगांठ!

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

वि

हार में जहरीली शराब से कम से कम 80 लोगों की मौत के बाद सवाल उठाने वालों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबी और पियककड़ करार दे रहे हैं, लेकिन क्या बिहार के मुख्यमंत्री पटना हाईकोर्ट को भी पियककड़ कहेंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णदु की बेंच ने 12 अक्टूबर को ये फैसला दिया था, नीरज सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में जस्टिस पूर्णदु सिंह की बेंच ने शराबबंदी के बहाने पूरे सरकारी तंत्र की कमाई की पोल खोली थी, हाई कोर्ट ने साफ कहा था कैसे

भरे शराब माफियाओं को बचाया जा रहा है और गरीबों की जिंदगी तबाह की जा रही है हाईकोर्ट ने कहा था।

दो महीने

पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार के अवैध शराब कारोबार की परत दर परत कलई खोल दी थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है ये पुलिस उत्पाद अधिकारियों,

ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ टैक्स बसूलने वाले विभाग के अधिकारियों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ-साफ कहा था कि शराब के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में है हाईकोर्ट ने 20 पन्ने के अपने फैसले में शराब पर सरकार को नंगा कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार निश्चित हो निश्चित होकर सोए रही। शराबबंदी के बाद बिहार में लगातार बड़ी संख्या में जहरीली शराब त्रासदी देखी गई है। यह सबसे चिंताजनक पहलू है जिस पर इस अदालत ने गौर किया है, न केवल जहरीली शराब बल्कि अवैध नशीली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग से भी लोगों का जीवन खतरे में है।

और जहरीली शराब बल्कि अवैध नशीली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग से भी बिहार के लोगों का जीवन खतरे में है। 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट के फैसले में साफ तौर पर कहा गया था। इस न्यायालय ने पाया है कि बिहार मध्य निधेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रवधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्यतंत्र की विफलता से नागरिकों की जीवन खतरे में है। शराबबंदी अधिकारियों के लिए मोटे पैसे का खेल है। अब विस्तार से पढ़िए 12 अक्टूबर 2022 को पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिहार का पूरा सरकारी सिस्टम शराबबंदी कानून के तहत गरीबों

आबकारी अधिकारी, बल्कि कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शराब से प्यार करते हैं, उनके लिए यह रकम है। शराब पीने वाले गरीबों और उनसे जुड़े गरीब लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की तुलना में किंगपिन/सिडिकेट संचालकों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या कम है, अधिनियम के प्रकाप का सामना कर रहे राज्य के अधिकांश गरीब वर्ग का जीवन दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपने परिवार के केवल कमाने वाले सदस्य हैं, नीतीजा परिवार के सदस्यों के भूखे मरने की नौबत आ गई है, जांच एजेंसी जानबूझकर कानून के अनुसार तलाशी जब्ती और जांच न करके माफिया को सबूत के

अभाव में मुक्त कर देती है। जहरीली शराब पर कोर्ट ने जताई थी गंभीर चिंता। 12 अक्टूबर

को ही पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल युक्त अवैध शराब पीने वालों ने अपनी जान गवाई है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 5 मिलीलीटर मिथाइल अल्कोहल एक आधा बनाने के लिए पर्याप्त है और 10 मिलीलीटर से

अधिक अक्सर घातक होता है। नकली शराब से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शराबबंदी के बाद राज्य में बड़ी संख्या में जहरीली शराब त्रासदी देखी गई है, यह सबसे चिंताजनक पहलू है जिस पर इस अदालत ने गौर किया है, न केवल जहरीली शराब बल्कि अवैध नशीली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग से भी लोगों का जीवन खतरे में है।

शराब के खेल में पुलिस और राजनेताओं की सांठगांठ, हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को ही अपने फैसले में कहा था। बिहार राज्य में शराब की संगठित तस्करी हुई है इसमें राजनीतिक



को फैसले में लगा है, न केवल पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी बल्कि राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शराबबंदी से प्यार करते हैं उनके लिए यह मोटी रकम है हाईकोर्ट ने कहा था।

जांच एजेंसी जानबूझकर शराब तस्करों को या गिरोह संचालकों के खिलाफ चार्ज शीट पेश नहीं करती है बल्कि गरीब चालक, क्लीनर, शराब की लोडिंग और अनलोडिंग में लगे मजदूरों और कभी-कभी, राहगीर जिनका उस अपराध से कोई संबंध भी नहीं है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है, न केवल पुलिस अधिकारी,

कनेक्शन वालों और पुलिस के साथ तस्करों का श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ाव है। पुलिस और अन्य अधिकारी जानबूझकर विभिन्न तस्करों और सिंडिकेट संचालकों के संबंध में सबूत नहीं देते हैं। शराबबंदी ने वास्तव में शराब और अन्य प्रतिबंधित सामानों के अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया है। शराब खुले रूप से उपलब्ध है तस्करों से सांठगांठ करने वाली पुलिस के लिए एक कठोर प्रधान आसान हो गया है।

१ सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ करवाई नहीं करती :- हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा है जिन अधिकारियों की सांठगांठ के बिना शराब तस्करी संभव नहीं है उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कर्रवाई करने में राज्य सरकार विफल है, राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों, आबकारी अधिकारियों, वाणिज्य कर अधिकारियों और संबंधित जिले के जिला परिवहन अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी और अनुशासनात्मक कर्रवाई करनी चाहिए।

२ बिहार में ड्रग्स का सेवन खतरनाक तौर पर बढ़ा है :- पटना हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा है बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद कई लोगों ने इसके विकल्प की तलाश शुरू कर दी, सरकार की सतर्कता न होने के कारण नशीले पदार्थों की आसानी से एट्री हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार सस्ती दवाओं की लत शराब का विकल्प बन गया, आंकड़े से पता चलता है कि 2015 से पहले ड्रग्स से संबंधित शायद ही कोई मामला था, लेकिन 2015 के बाद से यह खतरनाक रूप से बढ़ गया है अधिक चिंताजनक प्रवृत्ति यह है कि अधिकांश नशेड़ी 10 वर्ष से कम और 25 वर्ष से कम आयु के हैं। आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के बाद गांजा, भांग की लत तेजी से बढ़ी है, राज्य सरकार पूरे बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में विफल रही है।

३ शराबबंदी से लोगों की कार्य क्षमता में कमी आई :- हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 के अपने फैसले में कहा है शराबबंदी ने सस्ती जहरीली शराब और नशीले पदार्थों की खपत को ना केवल अवैध शराब के समानांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है बल्कि शराब से कई और समस्याएं बढ़ी हैं, ये पाया गया है कि मामूली दिहाड़ी कमाने वाले मजदूरों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया जिसे वे बहन नहीं कर सकते थे और उन्हें कर्ज लेना पड़ा जो उन्हें और मौत के



मुंह में धकेल देता है, ये, दर्ज किया गया है कि अधिकांश 18 से 35 वर्ष के बीच के लोग शराब के आदी हैं, इस उम्र के लोग ही समाज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन अवैध शराब के कारण इस उम्र के लोगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक नैतिक, बौद्धिक विकास पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा है। इससे कार्य क्षमता का हास हुआ है।

पटना हाईकोर्ट ने अपने 20 पन्ने के फैसले में बिहार में न सिर्फ पुलिस और उत्पाद विभाग बल्कि ट्रांसपोर्ट से लेकर टैक्स वसूलने वालों की सारी कलई खोल दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के जीएसटी वसूलने वाले अधिकारियों की पोल खोली है। हाईकोर्ट ने कई उदाहरण देते हुए कहा है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने शराब ढाने वाली गाड़ियों के नाम पर फर्जी ई बिल जारी किये, जिन गाड़ियों को अवैध शराब लाने के कारण जप्त कर लिया गया उनकी जब्ती के बाद भी उसी गाड़ी के नंबर पर ही बिल जारी कर दिया गया कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है आश्चर्यजनक रूप से वाहनों की जब्ती के बाद ई वे बिल बनाए गये। इस तरह की धोखाधड़ी राज्य कर अधिकारियों, आबकारी अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों के सहयोग से खेली जा सकती है। शराब तस्करी में ट्रांसपोर्ट विभाग में शामिल। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि शराब तस्कर नकली

नंबर प्लेट वाली गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ शराब तस्करी बल्कि नकली नंबर प्लेट का उपयोग करने के लिए धारा 467 आईपीसी के तहत एक अलग मामला दर्ज करने की आवश्यकता होती है। इस कोर्ट ने राज्य और उसके अधिकारियों को जब्त किए गए वाहनों का विवरण देने के साथ-साथ उन सभी बाहनों का विवरण देने का निर्देश दिया था जो बिहार राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और जो बिहार राज्य के अंदर चल रहे हैं सरकार को कहा गया था कि वह ऐसे वाहनों को कि आगे से उपयोग ना हो इसका उपाय बताएं लेकिन आज तक इस संबंध में कोई उपाय या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है और इस न्यायालय को सूचित नहीं किया गया है।

पटना हाईकोर्ट के इस आदेश में कई उदाहरण के साथ बिहार में शराब तस्करी के रैकेट की सारी पोल खोली गई है जहरीली शराब के कारण लोगों की जिंदगी पर गंभीर खतरे को हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले ही जाहिर किया था। हाईकोर्ट ने एक-एक कर बताया कि कैसे पुलिस अधिकारी उत्पाद विभाग ट्रांसपोर्ट विभाग और जीएसटी अधिकारी शराब के खेल में मोटा माल कमा रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार सोई रही। कोर्ट की अवमानना का डर नहीं होता तो नीतीश कुमार उसे भी पियकड़ और शराबियों का साथी करार देते।

●

भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए सबों को संकल्प लेना होगा

किसी के पास रहने का जगह नहीं, किसी के पास चोरी के सामान रखने की जगह नहीं

● डॉ लक्ष्मीनारायण सिंह

भ्र

ष्टाचार देश में यदि बढ़ रहा है तो किसीकी जिम्मेदारी बनती है।

आजादी के 75 साल में इस सवाल का उठाना अपने आप में गंभीर बात है। आज भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री यदि चिंता जता रहे हैं तो देश अच्छी तरह से वस्तुस्थिति को समझ रहा है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी के पास रहने की जगह नहीं है और किसी के पास चोरी का माल रखने की जगह नहीं है। निःसंदेह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें मिलकर कदम उठाने होंगे। ईश्वर, सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा पत्र माध्यम बना है तो उसे व्यर्थ न जाने दें। मोदी ने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि 'न खाऊंगा, ना खाने दूँगा' का शाखनाद किया। दो बार के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए अनेक कठोर कदम उठाए गए। उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भ्रष्टाचार की जटिल से जटिल होती स्थितियों को देखते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संस्थाओं मंत्रालयों और नागरिकों के लिए 6 बिंदु का सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, जिसमें उनसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना के साथ जोड़ने का आवाहन किया है। प्रतिज्ञा आयोग ने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए विशेष अभियान के तौर पर पेश किया है राष्ट्र में भ्रष्टाचार के विरुद्ध समय-समय पर ऐसी प्रतिज्ञा एवं प्रशासनिक उपक्रम होते रहे हैं लेकिन उनका लक्ष्य और उद्देश्य शुद्ध न रहने से उनका दीर्घकालिक परिणाम संदिग्ध रहा है। प्रश्न है कि सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या इसका हश्श ढाक के तीन पात ही होना है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी ही चाहिए, सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा पत्र 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक आयोजित किए जाने वाले भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत के जागृति अभियान का अभिनव उपकर्म है।



देव कुमार सिंह

इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह में तंद्रा तोड़ने के लिए भैरवी तो बजाने ही पड़ेगी। ईमानदारी के अभ्युदय के लिए इस प्रतिज्ञा पत्र में कहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करेंगे। नियमों का पालन करेंगे। कभी रिश्वत नहीं देंगे और न ही देंगे। सभी कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करेंगे। कभी रिश्वत नहीं देंगे और न ही देंगे। सभी कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करेंगे जनहित में कार्य करेंगे अपने आचरण में ईमानदारी दिखाएंगे। भ्रष्टाचार की घटना की सूचना संबंधित एजेंसियों को जरूर देंगे इस संकल्प निश्चित ही जन-जन और प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी संकल्प ले लेते तो भ्रष्टाचार समाप्त होने में दर नहीं लगेगी। लेकिन छोटे छोटे भ्रष्टाचार के साथ बड़े भ्रष्टाचार को भी नियंत्रण किया जाना जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुषी क्रांति का शंखनाद किया है जिससे प्रवर्तन निदेशालय आईडी एजेंसियां सक्रिय हुई हैं जिसने न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों एवं

उनके नेताओं के चूले हिला दी है बड़ी भ्रष्टाचार के ऊपर ही प्रशासन शक्ति को जागृत कर दिया है। रिश्वत एक नासूर है रिश्वत देने वाला काम जल्दी होने की उम्मीद में रिश्वत ले रहा है लेने वाला काम करने के बदले रिश्वत ले रहा है कि भ्रष्ट व्यवस्था कायम है काम में विलंब या आम आदमी को परेशान करना या भ्रष्टाचार को पोषित करने की जमीन है भले ही अपेक्षित सरे काम करना सरकारी कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी हो, फ्री भ्रष्टाचार को शिष्टाचार एवं रिश्वत को एक तरह से सुविधा शुल्क मान लिया गया है और इस के लेनदेन को लेकर कहीं कोई अपराध बोध नहीं दिखाई देता, ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाए। क्यों प्रतिज्ञापत्र की जरूरत है?

एक कहावत है कि सच जब तक जूतियां पहनता है, झूठ पूरे नगर का चक्कर लगाता है। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि राजनीति के शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठता है उसकी दृष्टि जन पर होनी चाहिए, पार्टी पर नहीं, धन पर नहीं। आज जन एवं राष्ट्रहित पीछे छूट गया और स्वार्थ आगे आ गया है जिन राजनीतिक दलों को जनता के हितों की रक्षा के लिए दायित्व मिला है अपने उन कार्यों और कर्तव्यों में पारदर्शिता रखे तो किसी भी ई डी, सीबीआई कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी और नहीं किसी सत्य निष्ठा प्रतिज्ञापत्र की जरूरत नहीं होगी। डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि प्रखंड, अंचल आदि में कार्य का समय निर्धारित कर भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। उदाहरण दाखिल - खारिज एक महीना, जाति, आय, निवास आदि के लिए एक सप्ताह निर्धारित कर देना चाहिए कि यदि विलंब होता है तो समझा जाएगा कि रिश्वत के लिए रोका गया है तथा उसका एक ही सजा जेल होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं विकास से जुड़े सभी अधिकारी को साल में एक बार नारको टेस्ट करवाना अनिवार्य करना होगा। नारको टेस्ट लागू होते हैं भारी बदलाव हो सकता है। ●

अपराध शोकना स्थकार का काम, पुलिस का नहीं : अनिल कुमार शर्मा

● डॉ लक्ष्मीनारायण सिंह

अ

पराध करने के लिए हथियार और कारतूस की आवश्यकता होती है। हथियार भले ही नकली होती है परंतु कारतूस सरकारी ही होती है। कारतूस की बिक्री रोकना सरकार का काम है। सरकारी कारतूस अपराधी को मिलना बंद हो जाए तो अपराध कैसे होगा। पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ कारतूस वापस करना पड़ता है तथा कारतूस इस्तेमाल करने का कारण बताना होता है कि किसके आदेश से इस्तेमाल किया गया इसका भी पूरा विवरण पुलिस को देना पड़ता है। सरकार पब्लिक को जो कारतूस उपलब्ध कराती है उसे इस्तेमाल करने के लिए किसी से आदेश नहीं लेना पड़ता है और नहीं इस्तेमाल किया हुआ कारतूस वापस करना पड़ता है। यदि कारतूस वापस करना पड़ता तो इस्तेमाल करने के पहले हजार बार सोचना पड़ता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध रोकने के लिए सरकार को सबसे पहले अवैध हथियारों के निर्माण और उपयोग पर कठोर ढंग से कार्रवाई करना चाहिए तथा हर गांव में पहले की तरह चौकीदार की बहाली करना चाहिए ताकि पुलिस तक सही जानकारी पहुंच सके। चार दशक पहले महिलाएं कोलकाता से पेशावर तक घूम लेती थीं, उस महिला की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। पुलिसकर्मी इमानदार होते थे, समाज के बड़े लोग हो या छोटे उसे पकड़ने में अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे, संस्कारों से लैस पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति इतने वफादार होते थे कि सफेदपोश



तथा कथित लोगों को बेनकाब पल भर में उतार डालते थे परंतु आज की पुलिस के पास ज्ञान भी है, वर्दी भी है और अधिकार भी है परंतु संस्कार के अभाव है। यदि बौर मूर्ति के मंदिर हो तो किसे आराधना करेंगे। बागर संस्कार वाली पुलिस का ही नतीजा है कि पहले एक चौकीदार से अपराधी जितना भय खाता था उतना भय बड़े-बड़े अधिकारियों से भी नहीं होता। आज जहां कभी अपराध नहीं हुए थे वहां भी आज मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है अकारण झूठे मुकदमों में फंसा कर हवालात के शिकंजे में कैद किया जा रहा है। संस्कार से लैस पुलिस कर्मियों को भी नहीं भुलाया जा सकता है जो वर्तमान व्यवस्था में भी आदर्श बन कर आए हैं ऐसे पुलिसकर्मियों से अन्य पुलिसकर्मियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ●

पुलिस अधिकारियों में किशोर कुणाल, किरण बेदी, डी.एन. गौतम, शोभा अहोतकर, रत्न संजय, विकास वैष्णव, शिवदीप लांडे वर्तमान बीजेपी राजविंदर सिंह भट्टी का नाम प्रत्येक नागरिकों के जुवान पर गूजता रहता है। फतुहा थाना में भी नवल सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, असरार अहमद, रघुनाथ सिंह, उद्धव सिंह, लक्ष्मण पासवान, के के साहू, वीरेंद्र कुमार मेयावी ने जो कर्मठता में जो उदाहरण कायम किया उसे यहां की जनता अभी भी याद करती है। वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के नाम सुनते ही पसीना छूटने लगी है, सभी आईपीएस को एक ही शिक्षा, एक ही वर्दी और एक ही अधिकार परंतु अधिकतर आईपी एस के लोग नाम तक नहीं जानते हैं। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें
और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल
सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769 / 9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

साइबर क्रिमिनल बन टाइम पारावर्ड हासिल कर सेंध लगा रहे हैं

● रीता सिंह

देखें

कौन में खाता खोलने के बाद दी जाने वाली वेलकम किट को भी साइबर अपराधी हथियार बना रहे हैं। वेलकम किट में दिए गए चेक बुक पर अकाउंट नंबर नहीं लिखा होता है, ऐसे में चेक की संख्या को खुरचकर विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए क्लोन तैयार कर लेते हैं। इसके बाद कस्टमर से किसी बहाने चेक के बारे में जानकारी हासिल कर क्लोन चेक से रकम पार कर देते हैं। वेबसाइट पर लिंक भेजकर सरकारी विभागों में नौकरी का विज्ञापन देखते ही, साइबर अपराधी वैसा ही फेक वेबसाइट तैयार कर लिंक के जरिए बेरोजगारों से रकम जमा करा रहे हैं। महज दस हजार रुपये और 6 से 7 घंटे में फेक वेबसाइट तैयार हो जाती है। इसके बाद लिंक में दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा कर जालसाज चंपत हो जाते हैं। इतना ही नहीं नौकरी के नाम पर ठगी के लिए टिक्टर, फेसबुक, वाट्सएप का भी इस्तेमाल हो रहा है। मुजफ्फरपुर रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि साइबर क्रिमिनल कम व्याज पर लोन का ज्ञांसा देकर भी खेल खेलते हैं। इन सभी से बचने के लिए जरुरी सावधानी अति आवश्यक है। एटीएम का इस्तेमाल करने से पहले आप यह देख लें कि एटीएम इंसरेन्च पैनल पर किसी की दूसरी वस्तु नहीं हो। ट्रांजैक्शन के समय एटीएम पिन नम्बर को हथेली से छुपा कर डालें और ट्रांजैक्शन रसीद बहां नहीं

छोड़ें। अपने एटीएम पिन को हर तीन महीने पर बदल दें, यह बैंक द्वारा दी गई सलाह है। क्रेडिट कार्ड रसीद को सुरक्षित रखें ताकि ट्रांजैक्शन की जालसाजी का पता लगा सकें। अपने रसीदों का मासिक विवरण से मिलान कर लें। केवल ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को साथ में रखें जिनकी आपको काफी आवश्यकता हो। ऐसे बिल जिन पर आपके क्रेडिट कार्ड का नम्बर दर्ज हो बारीक टुकड़ों में फाड़ दें। अपने घर को बदलने से पहले ही अपने कार्ड निर्गतकर्ता को पता बदलने की सूचना दे दें। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड खो देते हैं, तो कृपया उसकी सूचना तुरंत दें। अपग्रेडेशन के समय कार्ड को नष्ट करें तो उसे फेंकने के पहले हमेशा उसे एक कोने से दूसरे तक पूरी तरह से काट या तोड़ दें। बैंक से भेजा गया कार्ड अगर क्षतिग्रस्त हो या सील खुली होने की स्थिति में आए तो उसे स्वीकार न करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर पिन नम्बर नहीं लिखें। जिस क्रेडिट कार्ड का आप कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपने साथ न रखें। अपना क्रेडिट कार्ड नम्बर, एटीएम पिन किसी को न बताएं। अपना कार्ड किसी को न दें, भले ही वह अपनी पहचान बैंक कर्मचारी के तौर पर क्यों ना बताएं। किसी अजनबी द्वारा एटीएम मशीन में आपको मदद करने की पेशकश

के बहकावे में आने से बचें। किसी अज्ञात और अवैध स्रोत के साथ आप अपने खाते के विवरण को साझा न करें। किसी अनपेक्षित स्रोत से आए अजनबी ई-मेल एटेंचमेंट को न

खोलें या इन्स्टेंट मेसेज डाउनलोड लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी संदेहास्पद ई-मेल को तुरंत डिलीट कर दें। अपने खाता संख्या की जानकारी किसी को फोन पर तब तक न दें, जब तक कि आप कॉल करके यह सुनिश्चित कर लें कि अमुक कंपनी प्रतिष्ठित है। जब आपको कोई फोन कॉल आए और क्रेडिट कार्ड का विवरण मांगा जाए तो आप उसे कोई जानकारी न दें। किसी असुरक्षित वेबसाइट पर

आप कभी अपने क्रेडिट कार्ड का विवरण न दें। किसी भी ई-मेल में अपने खाते से संबंधित मांगी गई कोई भी गोपनीय सूचना जैसे कि पासवर्ड, कस्टमर आइडी, डेविट कार्ड नम्बर, पिन, सीवीवी, डीओबी की जानकारी कभी न दें, भले ही वह ई-मेल किसी भी सरकारी प्राधिकारों जैसे कि आयकर विभाग, आरबीआई या बीजा या मास्टर कार्ड से जुड़ी किसी कंपनी का ही क्यों न हो। अपने बैंक खाते से जुड़ी किसी समस्या या खाते के विवरण और पासवर्ड आदि किसी सोशल नेटवर्किंग साइट या ब्लॉग पर नहीं दें। अपने मोबाइल फोन में अपने एटीएम पिन नम्बर जैसे विवरण को सेव नहीं करें। ●



बिहार में नहीं चलेंगे दूसरे वाज्यों के नंबर वाले वाहन

● रीता सिंह

देखें

श में अब दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाले नंबर की गाड़ियां नहीं चलेंगी। प्रदेश सरकार ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। फिलहाल एक महीने का समय दिया गया है। अगर एक महीने बाद भी इस तरह के वाहन चलते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके मालिकों को 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हर शनिवार और रविवार को विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे वाहनों के चलने से नुकसान है।

जानिए, क्या है नया नियम :- मान लीजिए आपका दोपहिया या चारपहिया वाहन किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है और आप उसे बिहार में चला रहे हैं, वो भी बिना टैक्स का भुगतान किए तो पकड़ जाने पर आपको 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। यहां बता दें कि

ये नियम उनके लिए हैं, जो बिहार में रहते हैं और दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन बेधड़क चला रहे हैं।

बचने के लिए क्या करें :- अगर आप इस भारी भरकम फाइन से बचना चाहते हैं, तो 30 दिनों के अंदर अपने जिले के डीटीओ में रोड टैक्स जमा करवा दें। टैक्स जमा करने के बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। जिस राज्य में आपका वाहन रजिस्टर्ड है, उस राज्य में दिए गए टैक्स को वापस पाने के लिए वहां के परिवहन विभाग में क्लोम करना होगा। रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपको टैक्स की रकम वापस मिल जाएगी। दूसरे राज्य से एनओसी

मिलने के एक दो दिन बाद आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।

अगर आप अस्थायी रूप से बिहार आए हैं तो न घबराएं :- वैसे वाहन मालिक जो अस्थायी रूप से बिहार में आए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं। बस उन्हें कुछ बातों का खाल रखना होगा। जांच के दौरान दूसरे राज्य के पेट्रोल पंप की रसीद, टोल प्लाजा की रसीद या अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। ये दस्तावेज यह साबित करेंगे कि आप कूछ दिनों पहले ही बिहार आए हैं। यहां ध्यान रखें कि ये तमाम दस्तावेज 30 दिनों से अधिक पुराने न हों। वैसे वाहन मालिक जिनके पास बीच सीरीज का नंबर है, वो इस जुमाने से बच जाएगे। ●



अधिवक्ताओं में सामाजिक बदलाव लाने की है ताकत

● शिवानंद गिरी

अ

धिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, विद्वान साधु, संत, क्षमा, दान, ध्यान, दया, त्याग, एवं धैर्य का रूप माना जाता है परंतु क्या अब अधिवक्ताओं में ये सब गुण रह गए हैं? निसर्वेह ये सभी गुण पहले कभी अधिवक्ताओं में होते थे परंतु जिनमें सामाजिक बदलाव लाने की ताकत थी वह समय के बदलाव में सभी कुछ बदल गए, अधिवक्तागण पहले समाज सेवा के लिए एवं न्याय की आवाज बनने के लिए वकालत के क्षेत्र में आते थे परंतु अब सच्चाई यह है कि रोजगार के रूप में देखते हुए वकालत को नए युवा अधिवक्तागण इस व्यवसाय में आ रहे हैं और जब वे इस व्यवसाय में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वकालत करना इतना आसान भी नहीं है इसमें कई दशक अपने आप को स्थापित करने में बीत जाते हैं, जब जिंदगी जीने



का समय होता है उस वक्त वह संघर्ष करते हुए बुद्धापे की ओर बढ़ जाते हैं और जब बुद्धापा में उनकी वकालत चलती भी है तो उनकी किसी भी सपने को सच करने का समय उनके पास नहीं होता है। बहुत सारे अधिवक्तागण अपने स्वाभिमान एवं मान सम्मान को ताक पर रखकर वकालत में वे हर हथकंडे अपनाते हैं जो उन्हें नहीं अपनाने चाहिए या यूं कहें कि जो वह कॉलेज के दिनों में लॉ बुक्स को पढ़े हैं। वह लॉ बुक्स में लिखी गई बातें व्यवहारिक धरातल पर वकालत करने में इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि जो वाकई में विद्वान अधिवक्तागण होते हैं जिन्हें कानून की गहराई से जानकारी होती है उनसे दलाल काम करवा कर उन्हें थोड़ी सी राशि देकर सारी राशि वे अपने पास खुद रख लेते हैं और इस तरह से काम कोई और करता है नाम किसी और का होता है, इन्हीं सब बातों को देखते हुए अधिकांश अधिवक्तागण बहुत निराश हो गए हैं क्योंकि उनका सीधे संपर्क क्लाइंट से नहीं हो पाता है हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूर्व में वकालत में ऐसा नहीं होता था सच्चाई यह है कि पूर्व में भी कुछ लोग इस प्रकार की वकालत करते थे। गौरतलब है कि पूर्व में वकालत करने के लिए अधिवक्ता जर्मिंदार घरानों से या कहें उच्च घरानों से ही आते थे कालांतर में बेरोजगारी की समस्या एवं पढ़ने लिखने वालों की संख्या जब बढ़ी तो छात्र वकालत के क्षेत्र में व्यवसाय करने के उद्देश्य से भी आने लगे।

आज न्यायालयों में व्याप्त दोषपूर्ण



व्यवस्था के कारण भी अधिवक्तागणों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया है क्योंकि कुछ अधिवक्तागणों का बेल न्यायालयों में पहले सुन लिया जाता है और कुछ अधिवक्तागणों का फाइलिंग पकड़ाने में कई महीने लग जाते हैं, इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था के कारण भी अधिवक्तागणों में असंतोष व्याप्त हो गया है, फेस वैल्यू एक शब्द न्यायालयों में बहुत प्रचलित है वह फेस वैल्यू ही दोषपूर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है न्यायालयों में जिस प्रकार का कंप्यूटरीकरण हुआ है उसकी दोषपूर्ण व्यवस्था तो सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं में असंतोष पैदा करती है क्योंकि अधिकांश केस के रिकॉर्ड का डेट सीआईएस पर गलत चढ़ा हुआ है जिसके आधार पर रिकॉर्ड को खोजने में अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है साथ ही माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डे टूडे का आर्डर शीट भी ऑनलाइन सीआईएस पर चढ़ाना है परंतु ऐसा नहीं हो रहा है व्यवहार न्यायालय में लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड एवं सीसीटीवी कैमरा कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ और कभी स्टार्ट हुआ भी तो आज के डेट में अधिकांश सीसीटीवी कैमरा बंद है और डिस्प्ले बोर्ड तो केवल कोर्ट रूम की शोभा बनी हुई है उससे किसी भी अधिवक्ताओं को कोई फायदा आज तक नहीं हुआ है सिविल कोर्ट का रिकॉर्ड नाजायज क्लर्क के भरोसे चल रहा है, मोटी वेतन पाने वाले ओ/सी, बी/सी नाजायज क्लर्क रखकर कोर्ट का काम करवा रहे हैं।

सभ्य समाज के निर्माण में अधिवक्ताओं एवं विद्यि की भूमिका

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में एक सभ्य समाज के निर्माण में विद्यि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उस वक्त जब अंग्रेज के कानून देश पर लागू नहीं थे तब भारत के महान ऋषि मुनियों के ग्रंथ, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, संहिता इत्यादि के द्वारा समाज को दिशा निर्देश दिए जाते थे, जिसमें प्राचीन काल के कवि, लेखक, गायक इत्यादि का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, जिसमें वे जीवन दर्शन के सिद्धांत की चर्चा करते थे। वे साहित्य समाज को दिशा निर्देश देते थे और लोगों में नैतिक शिक्षा आचार-विचार, व्यवहार को सुदृढ़ और शुद्ध रखने की शिक्षा दी जाती थी। कुछ मुहावरों लोकउक्ति का भी प्रचलन था, जिससे समाज के लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में बताया जाता था। वैसे

ग्रंथ, साहित्य, वेद, पुराण लिखने वाले ही कानून बताते थे जो समाज के लोगों को शिक्षा एवं मार्गदर्शन देते थे साथ ही उन्हें यह भी बताते थे कि अगर कोई गलत काम करेंगे तो ईश्वर उन्हें इसी धरती पर दंड देगा तथा अच्छे काम करने पर निश्चित रूप से उन्हें इसका फल अच्छा मिलेगा। गीता में भी लिखा गया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान् यह है गीता का ज्ञान परंतु अब समय बदला हमारे देश में अंग्रेजों का हुक्मत आया और अंग्रेज ने भारतीयों पर शासन करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट हमारे देश में लाया जिसकी व्याख्या करने के लिए अधिवक्तागणों की जरूरत पड़ी।

पूर्व के ऋषि मुनि ही आज के अधिवक्ता वर्ग कहे जा सकते हैं जिनका प्रमुख काम निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाने में मदद करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हमारे देश में करीब ढाई सौ कानून हैं जिसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है विभिन्न प्रकार के कानून रहने की वजह से मुकदमों की संख्या भी बढ़ती है और सभी व्यक्ति को कानून की जानकारी होना संभव नहीं है फिर भी कानून यह मानती है कि सभी व्यक्ति को कानून की जानकारी है, अगर कोई व्यक्ति कानून की जानकारी के अभाव में कोई गलत काम कर देता है तो वह न्यायालय में यह कह कर नहीं बच सकता है कि उन्हें इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्हें जानकारी के अभाव में यह गलती हो गई। कानून इंसान की जन्म लेने के पहले और उसके मृत्यु के बाद भी उस पर अपना प्रभाव डालता है जैसे जब कोई बच्चा मां के गर्भ में आ जाता है तो उस वक्त से ही उस बच्चे की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना शुरू कर देता है साथ ही किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी उनके दादा परदादा तक की भी वसीयत को

साबित करने के लिए वंशावली की आवश्यकता पड़ती है जिसमें उनके दादा परदादा तक का नाम की खोजबीन की जाती है इस प्रकार से इंसान अगर घर में हो या बाहर हो सोया हुआ हो या जागा हुआ हो सांस ले रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो हर हाल में हर समय हर वक्त कानून का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता रहता है, इससे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है, इसलिए कानून की जानकारी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कानून को समाज नहीं मानते हैं और उसका विरोध करते हैं तो यह भी आवश्यक है कि कानून वही होना चाहिए जो समाज के भलाई के लिए बना हो तथा समाज को यह समझ में आए कि वह कानून क्या है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ कानून रूढ़ि रीति-रिवाजों के आधार पर भी बनती है जिसका समाज बड़ा ही कड़ाई से पालन करता है तथा औरों से भी करवाता है। कानून संसद में बनते हैं जिसमें एक्सपर्ट की राय ली जाती है और काफी दिनों तक इसका मॉनिटरिंग होता है तब जाकर कानून धरातल पर आता है।

एक सभ्य समाज के निर्माण में कानून की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है साथ ही अधिवक्ताओं की भूमिका भी उतनी ही आवश्यक है अगर कानून

ना हो न्यायपालिका ना हो तो हमारा समाज एक जंगल बन जाएगा और जो व्यक्ति को हम लोग सामाजिक प्राणी कहते हैं वह जंगली जानवर बन जाएगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जंगल का कानून लागू हो जाएगा, इसलिए सभ्य समाज के निर्माण में एक अच्छे कानून, एक अच्छे अधिवक्ता, अच्छी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है, इसके लिए प्रजातंत्र एक अच्छा तंत्र माना जाता है साथ ही प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब वहां के निवासी शत प्रतिशत शिक्षित होंगे इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण शर्त है सभ्य समाज के निर्माण में, इसलिए सभी व्यक्ति को राजनीति शास्त्र की शिक्षा कानून की शिक्षा लेना आवश्यक होनी चाहिए साथ ही बहुत सारे ऑट डेटेड हो चुके कानून को समाप्त कर के कुछ प्रमुख कानून को ही देश में लागू करना चाहिए क्योंकि जितने प्रकार के कानून बनेंगे उतने प्रकार के मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी, झूठे मुकदमे बाजी को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी प्रशासन एवं न्यायपालिका की होनी चाहिए इसलिए एक सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकेगा जब समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति शिक्षित एवं अच्छे संस्कार के बनेंगे क्योंकि डंडे की डर से किसी को कानून का पालन नहीं कराया जा सकता है कानून का पालन हृदय से दिल से होनी चाहिए ना कि डर भय से।



ऐसा कहा जाता है कि न्यायालय के सामने सभी बगाबर होते हैं परंतु सच्चाई क्या ऐसा है? न्यायालयों में परिवारवाद वंशवाद इसका प्रमुख उदाहरण है। क्या न्यायाधीशों के बच्चे ही कानून के ज्यादा जानकार होते हैं और साधारण परिवार से आए हुए अधिवक्ता को कानून की कम जानकारी होती है जो वह जुड़िशरी का एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं? आप सर्वे करा कर देख लीजिए न्यायालयों में चाहे पेशकार, चपरासी या जुडिशल मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश जितने भी काम कर रहे हैं 50% से ज्यादा किसी न किसी प्रकार से न्यायाधीश के खानदान से जुड़े हुए हैं। न्यायालय में दोषपूर्ण व्यवस्था तो एक तरफ विद्यमान है ही दूसरी तरफ अधिवक्ताओं की संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार कौंसिल भी दोषपूर्ण व्यवस्था से अछूती नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष ही कोरोनावायरस के काल में अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अन्य स्टेट के बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया है यह किसी अधिवक्तागणों से छिपी हुई नहीं है और जब अधिवक्तागण खुलकर इस व्यवस्था का विरोध करने लगे तो अधिवक्ताओं की आवाज को बंद करने के लिए एक कानून लाने का प्रयास किया गया जिसमें न्यायपालिका या बार काउंसिल के किसी पदाधिकारी के खिलाफ बोलने वाले किसी भी अधिवक्ता पर कानूनी कार्रवाई करने एवं उनका बकालत का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया जिसका कठोर विरोध राष्ट्रीय स्तर पर सभी अधिवक्ता गणों ने किया और तब मजबूत होकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस कानून को वापस ली थी। हमारा संविधान भी बोलने के अधिकार देश के आम नागरिकों को देता है और अधिवक्ता तो समाज का आवाज होता है और उसे ही बोलने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करना एक जघन्य अपराध की तरह था जिस पर अधिवक्ताओं के मन में घोर असंतोष, एवं निराशा व्याप्त हो गई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार कौंसिल या जिला अधिवक्ता संघ कोई भी अपने आमदानी एवं खर्चों का डीटेल्स अपने वेबसाइट पर अँनलाइन नहीं ढालती है ताकि ट्रांसपरेंसी हो सकें 24 सितंबर 2022 को पटना के बापू सभागार में बीसीआई एवं बिहार स्टेट बार काउंसिल ने संयुक्त रूप से भव्य कार्यक्रम कराया था जिसमें अधिवक्ताओं के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे परंतु उसका परिणाम क्या निकला अधिवक्ताओं के खाने के बीड़ियों बायरल हुए, जिसमें उस कार्यक्रम



की कुव्यवस्था उजागर हुई। उस कार्यक्रम में सीजेआई साहब ने वकीलों के मान सम्मान में बहुत कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि 'वकीलों में सामाजिक बदलाव लाने की ताकत है'। जो देश की न्यायिक प्रक्रिया है उसके विरुद्ध जनाक्रोश जायज है, अभी हाल फिलहाल में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आईपीसी एवं सीआईपीसी में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट बनाकर पारिलायमेंट में पेश करने की बातें कहीं हैं जिससे कानूनी प्रक्रिया में बहुत बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में अधिवक्ताओं को 'ऑफिसर ऑफ द कोर्ट' के नाम से भी सम्मानित किया है और न्यायालय के प्रत्येक निर्णयों में अधिवक्ताओं के लिए 'लर्नेंड काउंसिल' या विद्वान अधिवक्ता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है परंतु सच्चाई क्या ऐसी है? केवल अधिवक्ताओं को खुश करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट यह मानती है कि 'एडवोकेट्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट' तो एडवोकेट एक्ट 1961 में 'अधिवक्ता' की परिभाषा में 'एडवोकेट्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट' शब्द को क्यों नहीं समाहित कर दिया जाता है, इस पर संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय को अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अधिवक्तागणों के बैठने, लाइब्रेरी, शौचालय एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए अस्पताल, दवा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है।

गौरतलब है कि आज तक जितनी भी राजनीतिक दलों हैं बनी है उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्रों में अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए एक भी स्कीम को नहीं रखा है और सभी

राजनीतिक दलों ने एक षट्यंत्र के तहत हर दल ने लीगल सेल का गठन कर के अधिवक्ताओं की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास किया है। अधिकांश अधिवक्तागण किसी पार्टी के लीगल सेल से जुड़े हुए हैं और वह अपने पार्टी के लाइन से हटकर कोई गलत बयान अपने पार्टी के खिलाफ नहीं दे सकते हैं, चाहे ऐसा करने से उनके अधिवक्ता भाइयों के हितों की हत्या ही क्यों ना हो जाए और इतना ही नहीं, हर राज्यों में अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए छोटे-बड़े दर्जनों अधिवक्ताओं के मंच, संगठन, परिषद, फोरम संस्थाएं इत्यादि बनाए गए हैं, जो अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किसी दूसरे अधिवक्ताओं के मंच संस्था की बातों का समर्थन नहीं करते हैं और इस बजह से अधिवक्तागण आपसी फूट एवं वैमनस्यता के बजह से भी संयुक्त एवं संगठित रूप से अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार कौंसिल या सरकार के सामने उठा पाते हैं। इसलिए अगर अधिवक्ताओं में सामाजिक बदलाव लाने की ताकत को मजबूत करना है तो सबसे पहले अधिवक्ताओं को मजबूत करना होगा एवं अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल में अच्छे एवं ईमानदार पदाधिकारी को चुन कर भेजना होगा। क्योंकि अधिवक्तागणों के पदाधिकारीगण ही अधिवक्ताओं के शुभचिंतक नहीं दिख रहे हैं। इसलिए अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि एक अच्छे विचारवान एवं अधिवक्ता समाज के हितों की रक्षा के लिए तत्पर अधिवक्ता हो, ना कि वह न्यायाधीशों एवं सांसदों की दलाली चापलूसी करने वाले। ●